

मुख्यमंत्री साय की घोषणा पर अमल, कुनकुरी में 1.01 करोड़ रुपये के दो विकास कार्यों को मिली स्वीकृति

जशपुर। मुख्यमंत्री श्री विष्णुदेव साय की घोषणा के अनुरूप जशपुर जिले के कुनकुरी नगर में दो महत्वपूर्ण विकास कार्यों के लिए कुल 1 करोड़ 1 लाख 64 हजार रुपये की अंतिम स्वीकृति प्रदान की गई है। इनमें सूर्य नमस्कार चौक और सामुदायिक भवन का निर्माण शामिल है। दोनों कार्यों की स्वीकृति मिलने से कुनकुरी में अधोसंरचना विकास और नागरिक सुविधाओं के विस्तार को नई गति मिलेगी।

मुख्यमंत्री श्री साय ने ग्राम कलिबा में

नवनिर्मित कलिबेश्वर महादेव मंदिर के प्राण-प्रतिष्ठा कार्यक्रम के दौरान इन दोनों विकास कार्यों की घोषणा की थी। मुख्यमंत्री की घोषणा के अनुरूप अब दोनों कार्यों को अंतिम स्वीकृति मिलने के साथ ही इनके निर्माण का मार्ग प्रशस्त हो गया है।

76.81 लाख रुपये से विकसित होगा सूर्य नमस्कार चौक

कुनकुरी के वार्ड क्रमांक 06 में



हनुमान टेकड़ी के पास सूर्य नमस्कार चौक का निर्माण किया जाएगा। इसके लिए 76.81 लाख रुपये की राशि स्वीकृत की गई है।

चौक के विकसित होने से नगर को एक आकर्षक और व्यवस्थित सार्वजनिक स्थल मिलेगा। यह नगर की पहचान को नया स्वरूप देने के साथ नागरिकों के लिए उपयोगी सामुदायिक स्थल के रूप में विकसित होगा।

24.83 लाख रुपये से बनेगा सामुदायिक भवन

वार्ड क्रमांक 06 में हनुमान टेकड़ी के पास ही सामुदायिक भवन का निर्माण भी किया जाएगा। इसके लिए 24.83 लाख रुपये की अंतिम स्वीकृति प्रदान की गई है। सामुदायिक भवन बनने से स्थानीय नागरिकों को सामाजिक, सांस्कृतिक एवं अन्य सामुदायिक आयोजनों के लिए सुविधाजनक स्थान उपलब्ध होगा।

मुख्यमंत्री की घोषणा पूरी होने पर नगरवासियों में खुशी

मुख्यमंत्री श्री विष्णुदेव साय की घोषणा के अनुरूप दोनों विकास कार्यों को स्वीकृति मिलने पर कुनकुरी नगरवासियों ने प्रसन्नता व्यक्त करते हुए मुख्यमंत्री के प्रति आभार जताया है। नगरवासियों का कहना है कि इन कार्यों के पूरा होने से स्थानीय स्तर पर नागरिक सुविधाएं बढ़ेंगी और कुनकुरी के विकास को नई गति मिलेगी।

बेतरतीब लटकते तार कोरबावासियों के लिए बने खतरा



कोरबा। देश और प्रदेश को बिजली से रोशन करने वाली ऊर्जाधानी कोरबा में विद्युत व्यवस्था की हालत लचर है। बेतरतीब तरीके से लटकते तारों और केबलों का मकड़जाल लोगों के लिए खुला खतरा बना हुआ है। कहीं ऊंचाई इतनी कम है कि इसान कूदकर छू ले तो कहीं किसी के गले में तार उलझने से जान तक पर बन आ रही है। कोरबा और आसपास के इलाकों में विद्युत व्यवस्था की अनदेखी और सुरक्षा मानकों के अभाव में पहले भी कई दर्दनाक हादसे सामने आ चुके हैं। पूर्व में विद्युत पोल पर काम करने के दौरान और कई बार करंट की चपेट में आने व अनियंत्रित वाहनों के खंभों से टकराने जैसी दुर्घटनाओं में लोगों की जान तक जा चुकी है। ट्रंसफॉर्मर में आग लगना, खंबे से चिंगारी झूटना आम बात है। इसके बावजूद विद्युत विभाग और संबंधित एजेंसियों की नींद नहीं टूट रही है। स्थानीय नागरिकों का आरोप है कि शिकायतों के बाद भी विभाग किसी बड़े हादसे का इंतजार कर रहा है।

आत्मनिर्भरता की मिसाल: खेती के साथ हुनर को ग्रामीण महिलाएं दे रही रपतार

कोरबा। ग्रामीण महिलाओं के सशक्तिकरण और स्वावलंबन की एक और प्रेरणादायक तस्वीर सामने आई है। जिले में चल रहे %सेवा संकल्प अभियान% के तहत आयोजित प्रदर्शनियों में ग्रामीण महिलाओं ने अपने हुनर और मेहनत से तैयार स्थानीय उत्पादों का प्रदर्शन किया। खेती-किसानी के साथ-साथ लघु उद्योगों से जुड़कर ये महिलाएं किस तरह अपने परिवार की आर्थिक स्थिति को मजबूत कर रही हैं, इसकी बागमर्ी इन स्टॉलों पर साफ देखने को मिल रही है।।ग्रामी अंचलों की महिलाओं ने यह साबित किया है कि पारंपरिक कृषि कार्यों के साथ अन्य व्यावसायिक गतिविधियों को अपनाकर आर्थिक रूप से आत्मनिर्भर बना जा सकता है। महिलाओं ने बातचीत के दौरान बताया कि कृषि का कार्य अमूमन मौसम और फसल चक्र पर निर्भर होता है, ऐसे में वर्षाभर नियमित आमदनी के लिए उन्होंने स्थानीय स्तर पर उपलब्ध प्राकृतिक संसाधनों का रुख किया है। प्रदर्शनी में शिरकत कर रही महिलाओं ने अपने हुनर का प्रदर्शन करते हुए बताया कि वे



स्थानीय स्तर पर मिलने वाले कच्चे माल से कई उपयोगी वस्तुएं तैयार कर रही हैं। ?बांस शिल्प कला, मिट्टी के उत्पाद, झाड़ू, कोसा धागा, अचार सहिय पर्यावरण के अनुकूल बांस से सजावटी सामान, टोकरियां और घरेलू उपयोग की कलात्मक वस्तुएं बनाई जा रही हैं, जिन्हें बाजार में अच्छे रिसॉस मिल रहा है। स्थानीय संसाधनों और घास-फूस के जरिए उच्च गुणवत्ता वाली झाड़ू तैयार कर ग्रामीण महिलाएं शहरी और स्थानीय बाजारों में आपूर्ति कर रही हैं। इसके अलावा विभिन्न स्व-सहायता समूहों के जरिए अन्य

स्थानीय उत्पादों का निर्माण भी बड़े पैमाने पर किया जा रहा है। ?शासन-प्रशासन के सहयोग से चलाए जा रहे सेवा संकल्प अभियान और विभिन्न मेलों-प्रदर्शनियों के माध्यम से इन ग्रामीण महिलाओं को एक ऐसा खुला मंच मिल गया है। जहां वे अपने उत्पादों को सीधे ग्राहकों तक पहुंचा पा रही हैं। इससे बिचौलियों की भूमिका खत्म होती है और उनके उत्पादों का उचित और सीधा मूल्य महिलाओं को मिलता है। बांस शिल्प, झाड़ू निर्माण और अन्य हस्तशिल्प कार्यों से जुड़कर ग्रामीण महिलाएं न केवल खुद लखपति दौदी बनने के सपने को साकार कर रही हैं, बल्कि अपने परिवार और समाज के लिए एक मिसाल भी पेश कर रही हैं। इस प्रकार की पहल से ग्रामीण अर्थव्यवस्था को नई गति मिल रही है और महिलाओं का आत्मविश्वास व सामाजिक रुतबा दोनों बढ़ रहा है। केंद्र संरकार और राज्य सरकार के द्वारा ग्रामीण अर्थव्यवस्था को मजबूती देने के लिए कई योजनाएं चलाई जा रही हैं। जिसका वास्तविक लाभ ग्रामीण महिलाओं को मिल रहा है।

छत्तीसगढ़

प्रमुख समाचार

कॉलेज प्रोफेसर पर आपत्तिजनक व्यवहार का आरोप

बेमेतरा। बेमेतरी जिले से एक हैरान करने वाला मामला सामने आया है, जहां एक कॉलेज के प्रोफेसर पर छात्राओं के साथ कथित तौर पर आपत्तिजनक व्यवहार करने का आरोप लगा है। छात्रों ने मामले की शिकायत कलेक्टर से करते हुए कार्रवाई की मांग की है। यह पूरा मामला शासकीय पी जी महाविद्यालय बेमेतरा से जुड़ा हुआ है। शिकायतकर्ता के मुताबिक, कॉलेज के प्रोफेसर जे पी रायान ने फोन पर छात्राओं के साथ कथित तौर पर अश्लील और आपत्तिजनक व्यवहार किया। शिकायत में यह भी कहा गया है कि छात्राओं ने मामले की जानकारी कॉलेज के प्राचार्य वीणा त्रिपाठी को दी, जिसपर प्राचार्य के द्वारा उल्टा छात्राओं को चुप रहने और कॉलेज की बात कॉलेज में निपटाने की बात कही। इसके बाद अब कलेक्टर कार्यालय में शिकायत देकर पूरे मामले की जांच कराने और दोषी पाए जाने पर कार्रवाई की मांग की गई है। फिलहाल शिकायत के आधार पर मामले की जांच और प्रशासनिक कार्रवाई का इंतजार है। अब देखना होगा कि जांच में क्या तथ्य सामने आते हैं।

इस्तीफे से खाली पोस्ट पर वेटिंग लिस्ट से नियुक्ति का अधिकार नहीं: छग एचसी

बिलासपुर। छग हाईकोर्ट ने भर्ती प्रक्रिया और वेटिंग लिस्ट को लेकर एक महत्वपूर्ण फैसला सुनाया है. हाईकोर्ट ने स्पष्ट किया है कि किसी चयनित उम्मीदवार के नियुक्त होकर सेवा में जॉइन करने के बाद उसके इस्तीफे से उत्पन्न रिक्ति को पिछली चयन सूची अथवा वेटिंग लिस्ट के आधार पर नहीं भरा जा सकता। ऐसी रिक्ति एक नई अथवा बाद में उत्पन्न हुई रिक्ति मानी जाएगी और उसे लागू भर्ती नियमों के अनुसार नई भर्ती प्रक्रिया के माध्यम से भरा जाना होगा। यह आदेश जस्टिस बिभु दत्ता गुरु ने भूपेश वर्मा एवं अन्य बनाम छत्तीसगढ़ शासन एवं अन्य से संबंधित याचिकाओं पर सुनवाई करते हुए पारित किया। याचिकाकर्ता भूपेश वर्मा और विकास कुमार गुप्ता ने जूनियर इंजीनियर के पद पर भर्ती के लिए आयोजित चयन प्रक्रिया में भाग लिया था. संबंधित भर्ती प्रक्रिया में चयन सूची वर्ष 2024 में जारी हुई, लेकिन याचिकाकर्ताओं का नाम चयनित अभ्यर्थियों की सूची में नहीं आया। बाद में चयनित अभ्यर्थियों में से कुछ उम्मीदवारों ने नियुक्ति प्राप्त करने और संबंधित पदों पर कार्यभार ग्रहण करने के बाद सेवा से इस्तीफा दे दिया।

इंद्रावती नदी में विगत 50 वर्षों में सर्वाधिक 12.39 मीटर जलस्तर पहुंचा

जगदलपुर। बंगाल की खाड़ी में उठे चक्रवाती तूफान के प्रभाव से बस्तर अंचल में हुई मूसलाधार बारिश के कारण इंद्रावती नदी में भीषण बाढ़ की स्थिति निर्मित हो गई। इंद्रावती नदी का खतरे का स्तर 8.3 मीटर निर्धारित है। इससे पूर्व खतरे का स्तर नदी में सर्वाधिक जलस्तर 9 जुलाई 1973 को 12.18 मीटर दर्ज किया गया था, जबकि कल इंद्रावती नदी का जलस्तर बढ़कर 12.39 मीटर के अपने सर्वाधिक स्तर पर पहुंच गया। इससे इंद्रावती नदी के पास शहरी इशाकों में जहां कभी भी इंद्रावती नदी के बाढ़ का पानी नही पहुंचा वहां के घरों में पानी प्रवेश कर गया, इससे बाढ़ प्रभावितों को सबसे अधिक नुकसान उठाना पड़ा है। अत्यधिक जलस्तर के कारण इंद्रावती नदी के तटवर्ती क्षेत्रों, विशेषकर नदी बोडना और भेजापदर जैसे गांवों के चारों ओर पानी भर गया और ये क्षेत्र सड़क मार्ग से पूरी तरह कट गए। आपदा की इस घड़ी में जिला प्रशासन, एसडीआरएफ एवं अन्य बचाव दलों द्वारा युद्ध स्तर पर राहत एवं बचाव कार्य संचालित किए गए।

गाएं बोड़ार में पूनम और जयकुंवर ने सम्भाल रखी है स्वच्छता की कमान

कोरिया। जिले के वनांचल जनपद सोनहत के ग्राम पंचायत बोड़ार में स्व सहायता समूह की दो दीदीयों ने अपनी कर्मठता से गांव में स्वच्छता की अलख जगा दी है। ग्राम विक्रमपुर में रहने वाली श्रीमती पूनम और श्रीमती जयकुंवर द्वारा बीते वर्ष से नितर समर्पण भाव से किए जा रहे स्वच्छता कार्य से पूरे गांव में सामूहिक अनुशासन और स्वच्छता के प्रति जागरूकता की समझ विकसित हुई है। अब यह गांव पहले से ज्यादा बेहतर और स्वच्छता से पूर्ण हैं। इस अभिनव पहल से गांव में वातावरण की शुद्धता के साथ प्रदूषण का खतरा भी नगण्य हो गया है। स्वच्छ भारत मिषन ग्रामीण के तहत गांव में कचरे का प्रबंधन करने के लिए घर घर कचरा कलेक्षण का कार्य आरंभ किया जाना था। ऐसे मे समूह से जुड़ी हुई कई महिलाओं ने पारिवारिक संकोच के कारण इस कार्य से अपने आप को अलग कर लिया। ऐसे समय में गांव की पूनम और जयकुंवर ने गांव में स्वच्छता के लिए कार्य करने पर सहमति प्रदान की। इस कार्य को लेकर उनको अलग अलग तरह से बातें भी सुनने को मिलीं।

महाकाल सेना की निःशुल्क ज्योतिर्लिंग यात्रा आज

राजनादगांव। महाकाल सेना राजनादगांव छत्तीसगढ़ द्वारा प्रतिवर्ष की परंपरा के अनुसार इस वर्ष भी धार्मिक यात्रा का आयोजन किया जा रहा है। संस्कारधानी राजनादगांव से मंगलवार 29 सितंबर को हावड़ा-मुंबई ट्रेन से लगभग 400 महाकाल भक्तों का जत्था महाश्वर स्थित तीन ज्योतिर्लिंगों के दर्शन के लिए रवाना होगा। यात्रा के दौरान भक्त त्यंबकेश्वर ज्योतिर्लिंग (नासिक), भीमाशंकर ज्योतिर्लिंग (पुणे) एवं घृष्णेश्वर ज्योतिर्लिंग (ओरंगाबाद) के दर्शन करेंगे। यात्रा में युवा, बुजुर्ग सहित विभिन्न वर्गों के श्रद्धालु शामिल होंगे। भक्तजन सामूहिक रूप से जय श्री महाकाल के जयघोष के साथ यात्रा करेंगे। महाकाल सेना द्वारा यात्रा में शामिल होकर भी भक्तजनों के लिए निशुल्क दर्शन की व्यवस्था की गई है। यात्रा पूर्ण करने के बाद सभी भक्तगण 3 अक्टूबर को बॉम्बे-हावड़ा ट्रेन से संस्कारधानी राजनादगांव वापस लौटेंगे। महाकाल भक्त पवन डागा एवं नीलू शर्मा ने बताया कि पिछले लगभग 25 वर्षों से सामूहिक रूप से धार्मिक यात्राओं का आयोजन किया जा रहा है।

खुली नाली दे रही है मौत को दावत, दो माह से निर्माण कार्य अधूरा

एमसीबी। मनेंद्रगढ़ के वार्ड नंबर 16 में नगर पालिका 44 लाख रुपए से नाली का निर्माण करवा रहा है। लेकिन ये नाली लोगों की सुविधा के बजाय परेशानी का सबब बन रही है। करीब दो महीने से निर्माण कार्य अधूरा है। 100 मीटर से अधिक लंबी नाली कई जगहों पर खुली छोड़ दी गई है।जिसके कारण जिन लोगों के घरों के सामने नाली खुली है,वहां हर समय हादसे का डर बना रहता है। स्थानीय लोगों का कहना है कि नाली निर्माण के दौरान पहले भी कई बार दुर्घटनाएं हो चुकी हैं, इसके बावजूद जिम्मेदारों ने कोई सुरक्षा के इंतजाम नहीं किए। स्थानीय लोगों के मुताबिक निर्माण कार्य शुरू होने के बाद से नाली कई जगह अधूरी पड़ी है। कहीं गड्ढा खुला है तो कहीं सरिया बाहर निकली हुई है। सबसे ज्यादा परेशानी उन परिवारों को हो रही है, जिनके घरों के ठीक सामने नाली का निर्माण किया



गया है। लोगों का कहना है कि घर से बाहर निकलते ही सामने खुली नाली होने के कारण बच्चों और बुजुर्गों के विशेष सावधानी बरतनी पड़ती है। बारिश के दौरान स्थिति और भी गंभीर हो जाती है, क्योंकि पानी भरने से नाली की गहराई और निकली हुई सरिया स्पष्ट दिखाई नहीं देती। निर्माण अधूरा होने के साथ ही नाली में पानी की समुचित निकासी भी नहीं हो पा रही है।कई घरों के ठीक सामने नाली का निर्माण किया

से आसपास दुर्गंध फैल रही है।लंबे समय से जमा पानी के कारण मच्छरों के पनपने का खतरा भी बढ़ गया है। मनेंद्रगढ़ शहर में खुली नालियां पहले भी जानलेवा साबित हो चुकी हैं।शहर में खुली नाली में गिरने से एक बुजुर्ग महिला की मौत होने की घटना सामने आ चुकी है। इसके बावजूद शहर के कई हिस्सों में आज भी

नालियां खुली पड़ी हैं।ऐसे में वार्ड नंबर 16 में घरों के सामने लंबे समय से खुली पड़ी नाली और बाहर निकली लोहे की सरिया को लेकर लोगों की चिंता स्वाभाविक है। एक तरफ नगर पालिका अध्यक्ष बारिश के बाद निर्माण पूरा कराने की बात कह रही हैं, वहीं सीएमओ ठेकेदार को नोटिस देने की बात कर रहे हैं। लेकिन जमीनी स्थिति यह है कि लोगों के घरों के सामने नाली खुली

पड़ी है और उसमें निकली लोहे की सरिया किसी भी समय गंभीर हादसे का कारण बन सकती है। स्थानीय लोगों का कहना है कि नगर पालिका को सिर्फ निर्माण पूरा कराने की चिंता नहीं, बल्कि निर्माण पूरा होने तक लोगों की सुरक्षा की भी जिम्मेदारी लेनी चाहिए।यदि दुर्घटना की आशंका पहले से दिखाई दे रही है तो सुरक्षा इंतजाम में देरी क्यों? वार्डवासियों ने नगर पालिका प्रशासन से मांग की है कि अधूरे नाली निर्माण को जल्द पूरा कराया जाए, खुली नाली के आसपास सुरक्षा घेरा लगाया जाए, बाहर निकली सरिया को सुरक्षित किया जाए और पानी की निकासी की समुचित व्यवस्था की जाए। अब देखने वाली बात यह होगी कि नगर पालिका प्रशासन इस समस्या का समाधान किसी दुर्घटना से पहले करता है या फिर हादसे के बाद जिम्मेदारी तय करने की कवायद शुरू होती है

वित्त मंत्री चौधरी बाढ़ प्रभावित क्षेत्रों के दौरे पर

सारंगढ़-बिलाईगढ़। प्रदेश के वित्त मंत्री एवं रायगढ़ विधायक ओपी चौधरी आज सुबह सारंगढ़-बिलाईगढ़ जिले के महानदी तटवर्ती सरिया तहसील क्षेत्र के बाढ़ प्रभावित गांवों का जायजा लेने पहुंचे। उन्होंने सबसे पहले सरिया स्थित कन्या शाला में बनाए गए बाढ़ राहत शिविर पहुंचकर प्रभावित ग्रामीणों से मुलाकात की और उनकी समस्याएं सुनीं। ग्रामीणों ने मंत्री के समक्ष आवास सहित अपनी आवश्यकताओं को रखा। मंत्री चौधरी ने ग्रामीणों से बाढ़ की स्थिति और राहत व्यवस्थाओं की जानकारी ली। राहत शिविर में ग्रामीणों से चर्चा के बाद चौधरी ग्राम बोरिदा पहुंचे। यहां से उन्होंने राहत एवं बचाव दल के साथ नाव में सवार होकर जलमग्न ग्राम ठेंगागुड़ी का रुख किया। ठेंगागुड़ी पहुंचकर उन्होंने बाढ़ प्रभावित ग्रामीणों से मुलाकात की और मौके पर स्थिति की जानकारी ली। इसके बाद मंत्री चौधरी ग्राम तोरा पहुंचे, जहां उन्होंने ग्रामीणों से चर्चा कर बाढ़ एवं जलभराव की स्थिति का जायजा लिया। राहत-बचाव में जिला प्रशासन का मैदानी अमला सक्रिय जिला प्रशासन द्वारा बाढ़ प्रभावित ग्रामीणों



की सुरक्षा को प्राथमिकता देते हुए प्रभावित क्षेत्रों में राहत एवं बचाव कार्य लगातार संचालित किए जा रहे हैं। कलेक्टर श्रीमती पद्मिनी भट्टाई साहू के निर्देश पर एसडीएम, तहसीलदार, पटवारी, पंचायत सचिव, रोजगार सहायक एवं ग्राम कौटवार सहित मैदानी अमला गांव-गांव स्थिति पर नजर रखे हुए है। प्रभावित ग्रामीणों को राहत शिविरों, शासकीय चौपालों तथा सुरक्षित स्थानों पर पहुंचाया गया है। राहत शिविरों में भोजन, स्वास्थ्य एवं अन्य आवश्यक व्यवस्थाएं सुनिश्चित की जा रही हैं।

संक्षिप्त समाचार

बारिश से फसल नुकसान उठाने वाले किसानों को साय ने दिया बड़ा दिलासा



बाढ़ की स्थिति से कई जगहों पर हुए फसल नुकसान पर मुख्यमंत्री विष्णु देव साय ने किसानों को बड़ा दिलाया दिया है। उन्होंने कहा कि फसल नुकसान का सर्वे होगा। हम स्वयं आकलन करने जा रहे हैं। आकलन के बाद मुआवजा दिया जाएगा। सुकमा के लिए रवाना होने से पहले मुख्यमंत्री विष्णु देव साय ने मीडिया से चर्चा में कहा कि बारिश की कारण कई जगह पर बाढ़ की स्थिति बनी है। बाढ़ प्रभावित क्षेत्र के लोगों से मुलाकात करने जा रहे हैं। फसल, मकान का नुकसान हुआ है। पीड़ित लोगों से मुलाकात करेंगे। वहीं सिंगापुर दौरे को लेकर मुख्यमंत्री ने कहा कि नई उद्योग नीति आने के बाद देश-विदेश में इन्वेस्टर मीट का आयोजन किया जा रहा है। इस कड़ी में 4, 5 और 6 अक्टूबर को सिंगापुर प्रवास पर रहेंगे।

रायपुर में लगेगा राज्यस्तरीय रोजगार मेला, सीएम साय बांटेंगे ऑफर लेटर

रायपुर। छत्तीसगढ़ के युवाओं के लिए राजधानी रायपुर में 7 और 8 अक्टूबर को राज्यस्तरीय रोजगार मेले का आयोजन किया जाएगा। मुख्यमंत्री विष्णु देव साय के मुख्य आतिथ्य में आयोजित कार्यक्रम में चयनित युवाओं को ऑफर लेटर वितरित किए जाएंगे। रोजगार मेले के लिए अब तक 36 नियोजकों और प्लेसमेंट संस्थाओं से 8,720 पदों की जानकारी प्राप्त हो चुकी है। इसमें अलग-अलग शैक्षणिक योग्यता और तकनीकी दक्षता रखने वाले युवाओं के लिए रोजगार के अवसर उपलब्ध होंगे। रोजगार मेले में 10वीं-12वीं पास से लेकर आईटीआई, डिप्लोमा, इंजीनियरिंग और स्नातकोत्तर योग्यता रखने वाले अभ्यर्थी शामिल हो सकते हैं। विभिन्न कंपनियों और संस्थानों में अलग-अलग पदों पर भर्ती के अवसर उपलब्ध कराए जाएंगे। रोजगार मेले में मैनुफैक्चरिंग, टेक्निकल, इंजीनियरिंग, इलेक्ट्रिकल, ऑटोमोबाइल, सेल्स एवं मार्केटिंग, बैंकिंग एवं फाइनेंस, ऑफिस वर्क, मानव संसाधन, कस्टमर सर्विस, हेल्थ एंड केयर, सिक्योरिटी, लॉजिस्टिक्स और डिलीवरी समेत कई क्षेत्रों में रोजगार के अवसर मिलेंगे। इच्छुक अभ्यर्थी रोजगार मेले में शामिल होने के लिए छत्तीसगढ़ के आधिकारिक ई-रोजगार पोर्टल पर पंजीयन कर सकते हैं। अभ्यर्थी https://www.erojgar.cg.gov.in/ पर जाकर आवश्यक जानकारी दर्ज कर अपना पंजीयन करा सकते हैं।

भारतीय संगीत में लता जी का अमूल्य योगदान सदैव याद किया जाएगा : चौधरी



में एक अमिट छाप छोड़ी है। वित्त मंत्री चौधरी ने कहा कि लता मंगेशकर ने दशकों तक अपनी मधुर आवाज से हिंदी सिनेमा के संगीत को नई ऊंचाइयां दीं। उनके स्वर में सजे असंख्य गीतों ने संगीत प्रेमियों के हृदय में विशेष स्थान बनाया और पीढ़ियों तक सुने जाने वाले कालजयी गीतों की समृद्ध विरासत देश को दी। उन्होंने कहा कि लता जी की आवाज में भारतीय संस्कृति, संवेदना और भावनाओं की अद्भुत अभिव्यक्ति थी। देशभक्ति के गीतों से लेकर भक्ति और भावप्रधान गीतों तक उनकी गायकी ने हर पीढ़ी को प्रभावित किया। संगीत के प्रति उनका समर्पण और साधना आने वाली पीढ़ियों के कलाकारों को सदैव प्रेरित करती रहेगी। मंत्री चौधरी ने कहा कि भारतीय संगीत और कला जगत में लता मंगेशकर का अमूल्य योगदान सदैव स्मरणीय रहेगा। उनकी जयंती पर उन्हें सादर नमन।

8.48 करोड़ की लागत से 30.70 किलोमीटर सड़कों का होगा निर्माण

रायपुर। महिला एवं बाल विकास तथा समाज कल्याण मंत्री एवं भटगांव विधायक श्रीमती लक्ष्मी राजवाड़े के प्रयासों से सूरजपुर जिले में दो महत्वपूर्ण सड़क निर्माण कार्यों को बजट स्वीकृति मिली है। कुल 30.70 किलोमीटर लंबी इन सड़कों के लिए लगभग 8 करोड़ 48 लाख 28 हजार रुपये का प्रावधान किया गया है। बजट विवरण के अनुसार, खर्च से चिकनी भंडारपारा तक 17.50 किलोमीटर सड़क के लिए 5 करोड़ 8 लाख 98 हजार रुपये और कुंजनगर से जमदई पटेलपारा तक 13.20 किलोमीटर सड़क के लिए 3 करोड़ 39 लाख 30 हजार रुपये स्वीकृत हैं। मंत्री श्रीमती राजवाड़े ने कहा कि बेहतर सड़कों में गांवों की विकास की आधारशिला हैं। सड़क संपर्क मजबूत होने से ग्रामीणों को शिक्षा, स्वास्थ्य, बाजार और रोजगार से जुड़ी सुविधाओं तक पहुंचने में आसानी होगी। उन्होंने कहा कि भटगांव विधानसभा क्षेत्र सहित सूरजपुर जिले में सड़क और अन्य मूलभूत सुविधाओं के विस्तार के लिए निरंतर प्रयास किए जा रहे हैं। दोनों सड़क कार्य पूर्ण होने पर संबंधित गांवों का प्रमुख मार्गों से संपर्क बेहतर होगा। इससे ग्रामीणों, किसानों और विद्यार्थियों का आवागमन अधिक सुगम होगा।

राजधानी/छत्तीसगढ़

बाढ़ प्रभावित क्षेत्रों का जायजा लेने सुकमा पहुंचे मुख्यमंत्री

रायपुर। मुख्यमंत्री श्री विष्णु देव साय आज बाढ़ प्रभावित सुकमा पहुंचे। मुख्यमंत्री ने बाढ़ एवं जलभराव से प्रभावित क्षेत्रों का दौरा कर जमीनी स्थिति का जायजा लिया और राहत केंद्रों में की गई व्यवस्थाओं का निरीक्षण किया। मुख्यमंत्री श्री साय ने राहत केंद्रों में रह रहे प्रभावित लोगों से मुलाकात कर उनका हालचाल जाना। उन्होंने जिला प्रशासन से बाढ़ की स्थिति, राहत एवं बचाव कार्यों तथा प्रभावित परिवारों को उपलब्ध कराई जा रही सहायता की जानकारी ली।

मुख्यमंत्री ने अधिकारियों को प्रभावित लोगों की सुरक्षा, भोजन, पेयजल, स्वास्थ्य सुविधा और अन्य आवश्यक व्यवस्थाएं सुनिश्चित करने के निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि संकट की इस घड़ी में राज्य सरकार प्रभावित परिवारों के साथ पूरी मजबूती से खड़ी है।

छत्तीसगढ़ में तीन दिन बारिश तबाही लेकर आई। कई जिलों में बाढ़ जैसे हालात बन गए। शहरों में पुल पुलियों के ऊपर से पानी बहने लगा। दुर्ग रायपुर का संपर्क कट गया। गरियाबंद धमतरी के कई गांवों का संपर्क जिला मुख्यालय से कट गया। ग्रामीण क्षेत्रों में कई घर बाढ़ के पानी से भर गए,

लोगों को सुरक्षित जगहों पर शरण लेनी पड़ी। शनिवार देर रात से बारिश की रफ्तार कुछ कम हुई। रविवार सुबह से बारिश थम गई, जिसके बाद अब हालात पटरी पर आने लगे हैं।

बीजापुर जिले मे लगातार बारिश और बाढ़ के बीच इन्द्रावती नदी पार माड़ क्षेत्र में फंसे पटवारी एवं सर्वेयर सहित 6 कर्मचारियों को जिला प्रशासन की त्वरित कार्रवाई से एयरलिफ्ट कर सुरक्षित बीजापुर लाया गया। जिला मुख्यालय पहुंचने के बाद सभी कर्मचारियों का जिला अस्पताल में स्वास्थ्य परीक्षण कराया गया, जिसमें सभी की स्वास्थ्य स्थिति सामान्य पाई गई। बता दें कि गिरदावरी सर्वे कार्य के लिए पटवारी एवं सर्वेयर का 6 सदस्यीय दल बड़ेपल्ली और गुट्टामंगी क्षेत्र में गया था। इसी दौरान लगातार बारिश के कारण नदी-नालों में जलस्तर बढ़ गया और क्षेत्र में बाढ़ की स्थिति निर्मित होने से कर्मचारी वहाँ फंस गए।

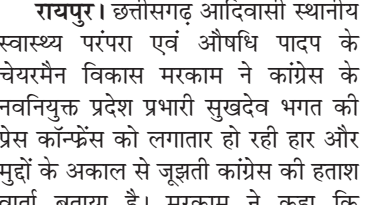
कर्मचारियों के फंसे होने की जानकारी मिलते ही कलेक्टर विश्वदीप ने तत्काल रेस्क्यू की कार्रवाई के निर्देश दिए। प्रशासन ने बिना समय गंवाए एयरलिफ्ट की व्यवस्था कर सभी 6 कर्मचारियों को सुरक्षित जिला



मुख्यालय पहुंचाया। जिला अस्पताल में कलेक्टर विश्वदीप की उपस्थिति में कर्मचारियों का स्वास्थ्य परीक्षण किया गया। कलेक्टर ने सभी कर्मचारियों से मुलाकात कर उनका कुशलक्षेम जाना और स्वास्थ्य संबंधी जानकारी ली। सुरक्षित लौटे कर्मचारियों के चेहरे पर राहत और अपनों से दोबारा मिलने की खुशी साफ दिखाई दी। कलेक्टर ने कठिन परिस्थितियों में अपने दायित्व का निर्वहन करने के लिए कर्मचारियों के कार्य की सराहना की।

कलेक्टर विश्वदीप ने कहा कि बाढ़ और आपदा की परिस्थितियों में जिला प्रशासन पूरी सजगता और तत्परता के साथ कार्य कर रहा है। प्रत्येक व्यक्ति की सुरक्षा प्रशासन की सर्वोच्च प्राथमिकता है। राहत एवं बचाव दल लगातार परिस्थितियों पर नजर बनाए हुए हैं,

पीसीसी प्रभारी सुखदेव भगत ने कांग्रेस की हताशा ही जाहिर की : विकास मरकाम



रायपुर। छत्तीसगढ़ आदिवासी स्थानीय स्वास्थ्य परंपरा एवं औषधि पादप के चैयरमैन विकास मरकाम ने कांग्रेस के नवनियुक्त प्रदेश प्रभारी सुखदेव भगत की प्रेस कॉन्फ्रेंस को लगातार हो रही हार और मुद्दों के अकाल से जुझती कांग्रेस की हताशा वार्ता बताया है। मरकाम ने कहा कि सुखदेव को, आदिवासियों को दुखदेव सिद्धांत पर चलने वाली पार्टी का प्रभारी बनाया गया है। अपने शासनकाल में कांग्रेस की भूपेश सरकार ने जिस प्रकार 32 प्रतिशत आरक्षण छीनने का प्रयास किया, हमारे हरा सोना तेन्दूपता के खरीदी को बंद किया गया, चरण पादुका छीनी गई, मूलभूत सुविधाओं के लिए तरसाया, आदिवासी राष्ट्रपति और आदिवासी मुख्यमंत्री को अपमानित किया गया उस दुःख और दंश को आजतक आदिवासी लोग नहीं हैं।

मरकाम ने कहा कि नाम सुखदेव लेकिन अपनी पहली ही प्रेस कॉन्फ्रेंस में ही बने झुठदेव। जिस प्रकार तारापुर कोल ब्लॉक को लेकर भगत ने झुठ बोला, वह



गो एरिया को गो एरिया बनाकर हसदेव अरण्य में खनन की नींव रखी, वन सलाहकार समिति (एफएसी) की आपत्तियों को दरकिनार तारा कोल ब्लॉक को स्टेज-1 मंजूरी दी। मरकाम ने कहा कि सत्ता में रहते बघेल सरकार ने हसदेव में कटाई और खनन प्रक्रियाओं को राजस्थान के गहलोत सरकार को बिजली देने के लिए आगे बढ़ाया और अब विपक्ष में रहते इसका विरोध कर रहे हैं। यह कांग्रेस के दोहरे चरित्र को दिखाता है। भूपेश बघेल ने मीडिया में कहा था, जिसे खनन से आपत्ति है वह अपने घर की बिजली बंद कर दें। यह बयान अभी तक छत्तीसगढ़ के लोग नहीं भूलें है।

मरकाम ने नसीहत देते हुए कहा कि भगत को सबसे पहले कांग्रेस में मची भयंकर गुटबाजी से लडना चाहिए, 36 गुटों में बैटी कांग्रेस को एकजुट करने की दिशा में चिंतन करना चाहिए। युवा कांग्रेस के ब्लॉक और जिलाध्यक्ष चुनावों में लेन-देन और भ्रष्टाचार पर चिंतन करना चाहिए। शराब घोटाला, पीएसी घोटाला, कोयला घोटाला, गोबर घोटाला में लिप्त नेताओं को छत्तीसगढ़ की राजनीति से दूर रखने की नीति पर चिंतन करना चाहिए। मरकाम ने कहा कि महतारी वंदन योजना, कृषक उन्नति योजना, लखपति दीदी योजना, नियद लागत के नेतृत्व में प्रदेश की भाजपा सरकार लगातार जनकल्याण के नए कीर्तिमान स्थापित कर छत्तीसगढिया को सबसे बढिया बनाने में जुटी है। इसकी चिंता सुखदेव जी को नहीं करनी चाहिए।

प्रदेशभर में कांग्रेस का प्रदर्शन, मुख्य चुनाव आयुक्त को हटाने की मांग

■ **रायपुर में निकाला पैदल मार्च, पीएम और ज्ञानेश कुमार का फूँका पुतला**

रायपुर। छत्तीसगढ़ में एसआईआर के मुद्दे और मुख्य चुनाव आयुक्त जोशेश कुमार के इस्तीफे की मांग को लेकर कांग्रेस ने सोमवार को राजधानी समेत प्रदेशभर में प्रदर्शन किया। रायपुर में पैदल मार्च निकालकर मुख्य चुनाव आयुक्त और प्रधानमंत्री मोदी का पुतला दहन किया। इस दौरान राजीव गांधी की प्रतिमा से कलेक्ट्रेट परिसर तक निकाले गए इस मार्च में प्रदेश प्रभारी सुखदेव भगत, प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष दीपक बैज और नेता प्रतिपक्ष चरणदास महंत समेत विधायक, पूर्व मंत्री और बड़ी संख्या में कार्यकर्ता शामिल हुए।

कांग्रेस की ओर से मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार को पद से हटाने और एफआईआर दर्ज करने की मांग की गई है। यह प्रदर्शन कांग्रेस के देशव्यापी विरोध कार्यक्रम का हिस्सा है, जिसमें पार्टी एसआईआर और मतदाता सूची से जुड़े



मुद्दों को लेकर चुनाव आयोग के खिलाफ प्रदर्शन कर रही है।

पैदल मार्च जब घड़ी चौक के पास पहुंचा तो पुलिस ने बैरिकेडिंग कर प्रदर्शनकारियों को रोक दिया। इस दौरान कांग्रेस कार्यकर्ताओं और पुलिस बल के बीच झुमाझुटकी की स्थिति भी बनी। मौके पर पुलिस बल तैनात है और प्रदर्शनकारियों को आगे बढ़ने से रोकने का प्रयास किया जा रहा है।

प्रदर्शन के दौरान कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार का पुतला दहन किया।कांग्रेस का कहना है कि एसआईआर और मतदाता सूची से जुड़े मुद्दों को लेकर वह अपना विरोध जारी रखेगी।

विचारों को उद्यम में बदलने का साहस रखें युवा : राज्यपाल

■ **तीन दिवसीय यूथ इनोवेशन एवं एंटरप्रेन्योरशिप कॉन्वलेव का शुभारंभ**

रायपुर। राज्यपाल श्री रमेन डेका ने कहा कि युवाओं को सिर्फ नौकरी पाने के बारे में नहीं सोचना चाहिए, बल्कि अपने विचारों को उद्यम में बदलने का साहस भी रखना चाहिए। एक अच्छा विचार, सही मार्गदर्शन और उपयुक्त तकनीक के साथ आगे बढ़े तो वही नवाचार सफल स्टार्टअप का रूप ले सकता है और आगे चलकर अनेक लोगों के लिए रोजगार का माध्यम बन सकता है।

राज्यपाल श्री डेका आज इंदिरा गांधी कृषि विश्वविद्यालय परिसर रायपुर में छत्तीसगढ़ के युवाओं में नवाचार, उद्यमिता विकास और प्रौद्योगिकी के व्यवसायीकरण को बढ़ावा देने के उद्देश्य से आयोजित तीन दिवसीय ‘यूथ इनोवेशन एवं एंटरप्रेन्योरशिप कॉन्वलेव-2026’ के शुभारंभ समारोह को संबोधित कर रहे थे। इस अवसर उन्होंने विश्वविद्यालय में स्थापित सुभाष चंद्र बोस बायोटेक्नोलॉजी इन्क्यूबेशन सेंटर का लोकार्पण भी किया।

राज्यपाल ने कहा कि हर क्षेत्र में नवाचार

ताकि किसी भी प्रकार की जनहानि को रोका जा सके और जरूरतमंदों तक समय पर सहायता पहुंचाई जा सके।

बाढ़ प्रभावित क्षेत्रों में राहत और बचाव कार्यों का जायजा लेने रायपुर कलेक्टर गौरव सिंह ने रविवार को विभिन्न इलाकों और राहत शिविरों का निरीक्षण किया। उन्होंने अधिकारियों को प्रभावित परिवारों को तत्काल आवश्यक सुविधाएं उपलब्ध कराने और राहत कार्यों में किसी भी तरह की लापरवाही नहीं बरतने के निर्देश दिए।

कलेक्टर ने नगर निगम आयुक्त संवित मिश्रा और जिला पंचायत सीईओ कुमार बिश्वरंजन सहित अधिकारियों के साथ श्रीलंका नगर बस्ती पहुंचकर बाढ़ की स्थिति का जायजा लिया। इस दौरान उन्होंने प्रभावित परिवारों से बातचीत कर उनकी समस्याएं और जरूरतें जानीं। कलेक्टर ने अधिकारियों को प्रभावित लोगों को हरसंभव सहायता उपलब्ध कराने के निर्देश दिए।

कलेक्टर ने पूर्व माध्यमिक शाला चांदनीडीह और शासकीय प्राथमिक शाला घनश्याम नगर डिपरपारा में बनाए गए राहत शिविरों का भी निरीक्षण किया। उन्होंने शिविरों में ठहरे लोगों से बातकर भोजन,

स्वास्थ्य सुविधाओं और अन्य आवश्यकताओं की जानकारी ली। प्रभावित परिवारों की राहत और पुनर्वास के लिए कार्ययोजना तैयार कर त्वरित कार्रवाई करने के निर्देश भी अधिकारियों को दिए।

कलेक्टर डॉ। सिंह ने कहा कि बाढ़ प्रभावित किसी भी नागरिक को परेशानी नहीं होनी चाहिए। राहत शिविरों में भोजन और राशन के साथ आवश्यक दवाइयों और कपड़ों की पर्याप्त व्यवस्था सुनिश्चित की जाए। उन्होंने संबंधित अधिकारियों को प्रभावित क्षेत्रों में हुए नुकसान का आकलन करने के निर्देश दिए। कलेक्टर ने कहा कि पात्र प्रभावित परिवारों को नियमानुसार क्षतिपूर्ति राशि प्रदान की जाएगी।

निरीक्षण के दौरान कलेक्टर गौरव सिंह, नगर निगम आयुक्त संवित मिश्रा, जिला पंचायत सीईओ कुमार बिश्वरंजन और डीसीपी पश्चिम रॉबिंसन गुड्डिया ने राहत शिविर में प्रभावित लोगों को वितरित किए जा रहे भोजन को स्वयं खाकर उसकी गुणवत्ता की जांच की। कलेक्टर ने भोजन की गुणवत्ता और स्वच्छता का विशेष ध्यान रखने के साथ प्रभावितों को नियमित रूप से भोजन उपलब्ध कराने के निर्देश दिए।

कोल घोटाला : 35 आरोपियों के खिलाफ 3 अक्टूबर को पेश होगी फाइनल चार्जशीट

■ **विधायक देवेंद्र याद से भी हुई पूछताछ**

रायपुर। छत्तीसगढ़ के बहुचर्चित कोल घोटाला मामले में आर्थिक अपराध अन्वेषण ब्यूरो (ईओडब्ल्यू) अब फाइनल चार्जशीट पेश करने की तैयारी में जुट गया है। 3 अक्टूबर को विशेष कोर्ट में मामले की फाइनल चार्जशीट पेश की जाएगी। इसे अंतिम रूप देने की प्रक्रिया तेज कर दी गई है।

बताया जा रहा है कि कोल घोटाला मामले में करीब 35 आरोपियों के खिलाफ चार्जशीट पेश की जाएगी। वहीं, अग्रिम जमानत हासिल कर चुके आरोपियों से भी ईओडब्ल्यू की पूछताछ का सिलसिला तेज हो गया है।

इसी कड़ी में कांग्रेस विधायक देवेंद्र यादव से भी ईओडब्ल्यू ने पूछताछ की है। उन्हें पूछताछ के लिए ईओडब्ल्यू कार्यालय बुलाया गया था, जहां करीब दो घंटे तक उनसे सवाल-जवाब किए गए।

छत्तीसगढ़ के चर्चित कोल घोटाला मामले की जांच ईओडब्ल्यू के साथ प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) भी कर रहा है। अब



ईओडब्ल्यू की ओर से विशेष कोर्ट में फाइनल चार्जशीट पेश किए जाने की तैयारी है। फाइनल चार्जशीट पेश होने के बाद इस मामले में आगे की न्यायिक प्रक्रिया तेज होने की उम्मीद है।

जांच एजेंसियों के मुताबिक, जुलाई 2020 से जून 2022 के बीच कोयला व्यापारियों और ट्रांसपोर्टों से हर टन कोयला परिवहन पर 25 रुपए की अवैध लेवी वसूली जाती थी। इसके लिए खनन विभाग के नियमों में बदलाव कर ऑनलाइन मिलने वाले कोल परमिट को ऑफलाइन किया गया। आरोप है कि इसके बाद एक सिंडिकेट ने परमिट व्यवस्था पर नियंत्रण कर अवैध वसूली का तंत्र खड़ा किया। ईडी और ईओडब्ल्यू की जांच के अनुसार, इस व्यवस्था के जरिए करीब 540 करोड़ रुपए से अधिक की अवैध वसूली की गई।



की आवश्यकता है। छत्तीसगढ़ में कृषि के क्षेत्र में नवाचार की व्यापक संभावनाएं हैं। देश की बढ़ती आबादी को खाद्यान्न आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए उत्पादन बढ़ाने के साथ नई तकनीकों और नए प्रयोगों को अपनाना जरूरी है। उन्होंने कहा कि प्रत्येक राज्य के लिए आवश्यक मूलभूत खाद्य पदार्थों के उत्पादन में आत्मनिर्भरता महत्वपूर्ण है। जब हमारी खाद्य आवश्यकताएं सुरक्षित होंगी, तभी हम विकास के अन्य क्षेत्रों पर अधिक प्रभावी ढंग से ध्यान केंद्रित कर सकेंगे।

उन्होंने कहा कि छत्तीसगढ़ में नवाचार की सबसे बड़ी संभावनाएं हमारे अपने संसाधनों में हैं। कृषि, वनोपज, खाद्य प्रसंस्करण, मिलेट, जैविक खेती, पशुपालन और जनजातीय उत्पादों जैसे क्षेत्रों में युवाओं के लिए अपार अवसर हैं। कृषि और जैव-प्रौद्योगिकी राज्य

मुख्य सचिव ने विभागीय सचिवों को समयबद्ध कार्ययोजना बनाकर कार्य करने के दिए निर्देश

धान खरीदी नीति से लेकर जल प्रबंधन और प्रशासनिक सुधारों की हुई समीक्षा

रायपुर। मुख्य सचिव विकासशील की अध्यक्षता में आज यहां मंत्रालय महानदी भवन राज्य शासन के सभी विभागों के भारसादक सचिवों की बैठक आयोजित की गई। बैठक में राज्य शासन के विभिन्न विभागों के अपर मुख्य सचिव, प्रमुख सचिव एवं सचिवों के साथ महत्वपूर्ण योजनाओं और विभागीय कार्यों की प्रगति की समीक्षा की गई। मुख्य सचिव ने अधिकारियों को निर्धारित कार्यों को समयबद्ध रूप से पूरा करने के निर्देश दिए हैं।

बैठक में धान खरीफ विपणन वर्ष के लिए सभी जरूरी व्यवस्थाएं करने के निर्देश दिए गए। लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी विभाग को पेयजल योजनाओं और जल संसाधन विभाग को शहरी एवं औद्योगिक क्षेत्रों में जल प्रबंधन और उपचार के लिए बेहतर कार्ययोजना तैयार करने को कहा गया है। नगरीय विकास विभाग को सिटी वाटर प्लान को विकसित भारत-2047 के बजट के अनुरूप तैयार करने के निर्देश दिए गए। ग्राम

सभा के आयोजन के लिए निर्धारित 15 से 22 अक्टूबर की अवधि में आवश्यक तैयारियां समय पर पूर्ण करने को कहा गया। परिवहन विभाग को आगामी समय में ई-व्हीकल को बढ़ावा देने पर विशेष ध्यान देने तथा खाद्य विभाग को सिटी गैस डिस्ट्रीब्यूशन पॉलिसी तैयार करने के निर्देश दिए गए।

मुख्य सचिव ने जिलों में योजनाओं और विभागीय कार्यों की प्रभावी निगरानी के लिए स्कोर कार्ड को अंतिम रूप देने को कहा गया, जिससे कलेक्टरों के स्तर पर प्रगति की नियमित मॉनिटरिंग की जा सके। उन्होंने कहा कि कोर्ट मॉनिटरिंग सिस्टम को प्रभावी बनाने तथा अक्टूबर माह के लिए पारस पोर्टल से संबंधित प्रस्तावों पर आईटी विभाग के साथ समन्वय कर आवश्यक कार्रवाई करने के निर्देश दिए।

मुख्य सचिव ने कहा कि शासन द्वारा बनाए गए सभी विधिक, नियमो, निर्देशों की संदर्भ प्रति ई-गवट पर अपलोड की जाए, ताकि अधिकारियों और संबंधित विभागों को



भविष्य में संदर्भ के लिए इनका आसानी से उपयोग किया जा सके। पेंशन से संबंधित मामलों की विभागवार समीक्षा करते हुए विभागध्यक्ष प्रत्येक विभाग को लॉबित प्रकरणों की संख्या, उनके निराकरण में लगे समय और प्रगति की रिपोर्टिंग सुनिश्चित करने के निर्देश दिए। एपीएआर को आईगॉट से लिंक करने तथा प्रत्येक विभाग को कर्मचारियों के क्षमता निर्माण की कार्ययोजना तैयार करने को भी कहा गया।

मुख्य सचिव ने कर्मचारी चयन मंडल के लिए विभिन्न विभागों में रिक्त पदों की जानकारी 30 सितंबर तक उपलब्ध कराने के निर्देश दिए। बैठक में लोक सेवा गारंटी अधिनियम, रिफॉर्म उत्सव, 2 अक्टूबर की ग्राम सभाओं की तैयारियों और सेवा सेतु की

प्रगति पर भी चर्चा हुई। बताया गया कि वर्तमान में 38 विभागों की 907 सेवाएं सेवा सेतु के माध्यम से ऑनलाइन उपलब्ध हैं। मुख्य सचिव ने फायर सेफ्टी अधिनियम में आवश्यक सुधार की दिशा में कार्यवाही करने के साथ ही माय भारत पोर्टल से संबंधित गतिविधियों को भी गति देने के निर्देश दिए।

बैठक में गुह विभाग की सचिव श्रीमती नेहा चम्पावत ने बताया कि एंटी नारकोटिक्स टास्क फोर्स के माध्यम से जानकारि एकत्रित की जाएगी और इसके बाद भारत सरकार को भेजी जाएगी। उन्होंने बताया कि इससे विभिन्न विभागों से प्राप्त सूचनाओं की समेकित रिपोर्टिंग सुनिश्चित होगी। मुख्य सचिव ने बैठक के अंत में सभी विभागों को क्षमता निर्माण, विभागीय कार्यों की निगरानी और निर्धारित लक्ष्यों को समयबद्ध पूर्ति के लिए स्पष्ट कार्ययोजना तैयार करने के निर्देश दिए।

बैठक में वन एवं जलवायु परिवर्तन विभाग के अपर मुख्य सचिव श्री मनोज

कुमार पिंगुआ,पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग की अपर मुख्य सचिव श्रीमती त्रुष्ठा शर्मा, गुह एवं जेल विभाग की प्रमुख सचिव श्रीमती निहारिका बारिक सिंह, विधि एवं विधायी विभाग के प्रमुख सचिव श्री मनोष कुमार ठाकुर, नगरीय प्रशासन विकास विभाग के प्रमुख सचिव श्री सोनमणि बोरा, महिला एवं बाल विकास विभाग की प्रमख सचिव श्रीमती शहला निगार, खनिज साधन विभाग एवं मुख्यमंत्री के सचिव श्री पी. दयानंद, मुख्यमंत्री एवं लोक निर्माण विभाग के सचिव श्री मुकेश कुमार, स्कूल शिक्षा विभाग के सचिव डॉ. कमलप्रीत सिंह, सूचना एवं प्रौद्योगिकी विभाग के सचिव श्री अंकित आनंद, ऊर्जा विभाग के सचिव श्री सारांश मिश्र, राजस्व एवं आपदा प्रबंधन विभाग की सचिव श्रीमती शम्मी आबिदी, लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी विभाग के सचिव मोहम्मद कैसर अब्दुल हक सहित राज्य शासन के अन्य विभागों के वरिष्ठ अधिकारी मौजूद थे।

यूपी में आपस में लड़ रहे इंडिया ब्लॉक

नीरज कुमार दुबे

दिल्ली में विपक्षी गठबंधन इंडिया के भीर एक बार फिर एकजुटता की कवायद तेज हो गयी है। चुनाव आयोग से संबंधित मुद्दे पर साझा लड़ाई लड़ने की तैयारी हो रही है, नेताओं के बीच बातचीत बढ़ी है और दिल्ली में सभी विपक्षी दलों की बैठक भी बुला ली गई है। लेकिन सियासत का असली सवाल यह है कि क्या दिल्ली की एकजुटता उत्तर प्रदेश की जमीन तक पहुंच पाएगी ? क्योंकि जिस गठबंधन को दिल्ली में एक मंच पर खड़ा करने की कोशिश हो रही है, उसी गठबंधन के सबसे बड़े चुनावी मैदान उत्तर प्रदेश में समाजवादी पार्टी और कांग्रेस के बीच खींचतान लगातार खुलकर सामने आ रही है। उल्लेखनीय है कि तृणमूल कांग्रेस नेता अभिषेक बनर्जी और लोकसभा में विपक्ष के नेता राहुल गांधी चुनाव आयोग के मुद्दे पर विपक्षी दलों को एक मंच पर लाने और उन दलों से संवाद बढ़ाने पर चर्चा कर रहे हैं, जो हाल के महीनों में कांग्रेस से दूरी बनाए हुए हैं। इसके साथ ही इंडिया गठबंधन के घटक दलों की बैठक बुलाने, संयुक्त प्रेस वार्ता और देशव्यापी साझा आंदोलन की संभावना पर भी बातचीत चल रही है। यानी ऊपर से संदेश यही है कि विपक्ष को फिर एक साथ खड़ा किया जाए। मगर हुजूर, राजनीति में असली परीक्षा मंच पर हाथ मिलाने की नहीं, मैदान में सीट बांटने की होती है। और यहीं से कहानी बदल जाती है। उत्तर प्रदेश में 403 विधानसभा सीटों का हिसाब किताब शुरू होते ही सपा और कांग्रेस के बीच पुरानी दोस्ती की परतें खुरचने लगी हैं। कांग्रेस ज्यादा सीटों की मांग कर रही है, जबकि समाजवादी पार्टी अपनी ताकत और पिछले चुनावी प्रदर्शन के आधार पर बड़ा हिस्सा अपने पास रखना चाहती है। दोनों दल अपने-अपने स्तर पर सीटों की ताकत-कमजोरी का आकलन कर रहे हैं और गंभीर सीट बंटवारे की बातचीत अक्टूबर में शुरू होने की संभावना बताई गई है। उधर, तनाव सिर्फ बंद कमरों की बातचीत तक सीमित नहीं है। कांग्रेस के इमरान मसूद ने जल्द गठबंधन तय करने की मांग की और कहा कि भ्रम की स्थिति में कांग्रेस चुनावी तैयारी नहीं कर सकती। कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष अजय राय ने तो यहां तक कहा कि मतभेद होने पर पार्टी सभी सीटों पर चुनाव लड़ने के लिए तैयार है। दूसरी तरफ सपा की सांसद इकरा हसन ने साफ कहा कि उत्तर प्रदेश में भाजपा को चुनौती देने की क्षमता अखिलेश यादव के नेतृत्व में है। इस तरह यानी एक ही गठबंधन में दो सुर, दो दावे और दो नेतृत्व केंद्र दिखाई दे रहे हैं। अखिलेश यादव का रायबरेली से पीडीए यात्रा शुरू करना भी इसी रस्साकशी का हिस्सा माना जा रहा है। रायबरेली कांग्रेस का पारंपरिक गढ़ रहा है, लेकिन अखिलेश ने वहीं से अपनी राजनीतिक यात्रा शुरू कर यह संदेश दिया कि उत्तर प्रदेश में जमीन किसके पास है, इसका हिसाब अलग से होगा। इसे कई राजनीतिक विश्लेषक सीट बंटवारे से पहले सपा की राजनीतिक ताकत दिखाने की कवायद के तौर पर देख रहे हैं। और अब मैनपुरी-इटाना-सैफई की धरती से शिवपाल सिंह यादव का बयान इस खींचतान में नया तड़का लगा रहा है। कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष अजय राय ने कहा था कि अखिलेश रायबरेली जा सकते हैं तो कांग्रेस भी इटाना, कन्नौज और मैनपुरी जाएगी। जवाब में शिवपाल ने कहा— जाइए, अभियान चलाइए, लेकिन वहां कोई कांग्रेस को वोट नहीं मिलेगा। अब शिवपाल के इस बयान का राजनीतिक मतलब समझिए। यह सिर्फ किसी एक रैली या दौरे पर प्रतिक्रिया नहीं है। यह दरअसल सपा के उस आत्मविश्वास का प्रदर्शन है जिसमें वह कांग्रेस को यह याद दिलाना चाहती है कि उत्तर प्रदेश में गठबंधन की जमीन सपा के संगठन और सामाजिक आधार से तैयार होती है।

भारतीय दार्शनिक सम्प्रदाय

9- बौद्ध दार्शनिक सम्प्रदायों का वास्तविक विभाजन

गतांक आगे...

(2) हीनयान के अन्तर्गत सर्वास्तित्वाद जिस के मुख्य सम्प्रदाय वैभाषिक के सिद्धान्तों का स्वरूप विशेषकर वसुबन्धु के अभिधर्मकोष में पाया जाता है, (3) नार्गार्जुन का माध्यमिक दर्शन या शून्यवाद (nihilism or relativism)

(4) असङ्ग और वसुबन्धु का योगाचार सिद्धान्त, जिसका स्वरूप ज्ञान वाद (idealism) है; (5) दिङनाग का %बौद्ध न्याय-वाद% जिसका विस्तार धर्मकीर्ति ने किया, इस सिद्धान्त को श्वेरबास्की ने सौत्रान्तिक अथवा सौत्रान्तिक-योगाचार भी कहा है।

यह स्पष्ट है कि बौद्ध-दर्शन का उपयुक्त विभाग कोई प्रामाणिक नहीं कहा जा सकता और न यह विभाग कहीं बौद्ध-ग्रन्थों में दिया गया है, परन्तु बौद्ध दर्शन के विषय में इस समय हमारी जो जानकारी है, उसके अनुसार इन्हीं बौद्ध दार्शनिक सम्प्रदायों के

सिद्धान्त ही हमारे सामने आर हैं।

उपयुक्तविभाजन में सौत्रान्तिक को दिङ्नाग सम्प्रदाय के अतिरिक्त अलग दार्शनिक सम्प्रदाय नहीं कहा गया है, कम से कम उस प्रकार का सौत्रान्तिक दर्शन, जिसका निरूपण सर्वदर्शनसंग्रह में किया गया है, (देखो परिच्छेद 6), बौद्ध दार्शनिक साहित्य में कहीं भी नहीं पाया जाता।

यह ठीक है कि बौद्ध साहित्य में सौत्रान्तिक नाम का एक प्रसिद्ध दार्शनिक सम्प्रदाय था, और वसुबन्धु के अभिवर्मकोष (जो कि एक वैभाषिक ग्रन्थ है) का टीकाकार यशोमित्र सौत्रान्तिक था, परन्तु दिङ्नाग से भिन्न कौन सा सौत्रान्तिक सम्प्रदाय था और उसके दार्शनिक सिद्धान्तों की रूपरेखा क्या थी, इसका पता अभी तक स्पष्ट रूप से नहीं लग सका है, यद्यपि सौत्रान्तिकों के कुछ फुटकर सिद्धान्तों का उल्लेख इधर उधर मिलता है।

क्रमशः...



ज्ञान/मीमांसा

राष्ट्राध्यक्षों द्वारा हिंदी गाने गाकर सांस्कृतिक जुड़ाव की रणनीति

प्रोफ़ेसर (डॉ.) डी. के. पांडेय

दिल्ली में हुए ब्रिक्स 2026 शिखर सम्मेलन के दौरान, मलेशिया के प्रधानमंत्री अनवर इब्राहिम ने दो लोकप्रिय हिंदी फ़िल्मी गाने गाकर सबका ध्यान खींचा। उन्होंने ख्वाब हो तुम या कोई हकीकत और दोस्त, दोस्त न रहा, प्यार प्यार न रहा गाने गाए। इससे पहले, फरवरी 2026 में प्रधानमंत्री मोदी की मलेशिया यात्रा के दौरान, अनवर ने कभी-खुशी कभी गम फ़िल्म के गाने बोले चूड़ियों के साथ अपना आधिकारिक वीडियो एडिट करके उसमें बॉलीवुड का तड़का लगाया था।

विदेशी नेता और अधिकारी लंबे समय से अंतरराष्ट्रीय कार्यक्रमों में हिंदी गाने गाते रहे हैं। जैसा कि कहा जाता है, संगीत की कोई भाषा नहीं होती। यह सीधे दिल से निकलता है। समय के साथ, कई गैर-भारतीय हस्तियों ने वैश्विक आयोजनों में हिंदी गाने गाकर दर्शकों का दिल जीता है। इसके कुछ उल्लेखनीय उदाहरण नीचे दिए गए हैं—

(1) अगस्त 2023 में, भारत में तत्कालीन ब्रिटिश उच्चायुक्त सर अलेक्जेंडर एलिस ने किशोर कुमार की जयंती के अवसर पर ब्लैकमेल (1973) फ़िल्म का गाना पल पल दिल के पास गाते हुए एक वीडियो पोस्ट किया। उन्होंने यह भी बताया कि उनकी पसंदीदा हिंदी फ़िल्में शोले और चुपके-चुपके हैं। यह सांस्कृतिक कूटनीति का एक बेहद व्यक्तिगत रूप था, क्योंकि ब्रिटिश राजनयिक ने खुद हिंदी गाना गाने में सक्रिय रूप से हिस्सा लिया था।

(2) 27 से 28 अप्रैल 2018 तक चीनी विदेश मंत्रालय द्वारा आयोजित वुहान शिखर सम्मेलन के दौरान, हुबेई संग्रहालय में एक कार्यक्रम में चीनी संगीतकारों ने भारतीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और राष्ट्रपति शी जिनपिंग के लिए हिंदी फिल्म ये वादा रहा (1982) के गाने तू तू है वही दिल ने जिसे अपना कहा की धुन (इंस्ट्रुमेंटल) बजाई। प्रधानमंत्री मोदी ने ट्वीट किया, विदेशी धरती पर भारतीय संगीत सुनकर बहुत अच्छा लगा... हमारे कलाकार दुनिया भर में लोकप्रिय हैं। दिवंगत ऋषि कपूर, जो मूल गाने में नज़र आए थे, भी ट्वीट किया, सम्मानित महसूस कर रहा हूँ।

(3)मार्च 2021 में, भारतीय राजदूत तरनजीत सिंह संधु के लिए आयोजित एक डिनर में, जिसमें अमेरिकी नौसेना के चीफ ऑफ नेवल ऑपरेशन्स एडमिरल माइकल गिल्डे भी शामिल हुए थे,



अमेरिकी नौसेना के आधिकारिक बैंड सी चैंटर्स ने हिंदी फिल्म स्वदेश (2004) का गाना ये जो देश है तेरा पेश किया। अमेरिकी नौसेना बैंड ने ट्वीट किया, नौसेना बैंड 1925 से ही नौसेना को सहयोगी देशों से जोड़ रहा है! होली की शुभकामनाएं। राजदूत संधु ने जवाब दिया, यह दोस्ती का ऐसा बंधन है जिसे तोड़ा नहीं जा सकता।

(4) 2019 में, महात्मा गांधी की 150वीं जयंती मनाने के लिए 124 देशों के संगीतकारों ने भक्ति गीत वैष्णव जन तो तेने कहिए की एक मेडली (कई धुनों का मिश्रण) पेश की। भारत के विदेश मंत्रालय की अगुवाई वाली इस पहल में आर्मेनिया से अंगोला और आइसलैंड से इराक तक के देशों के कलाकार शामिल थे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इसका संकलन वीडियो जारी किया।

राजनीतिक वैज्ञानिक इस घटनाक्रम को सांस्कृतिक कूटनीति या बॉलीवुड कूटनीति कहते हैं। इसमें सॉफ्ट पावर के एक साधन के तौर पर हिंदी सिनेमा का इस्तेमाल किया जाता है और कूटनीतिक प्रोटोकॉल के साथ सांस्कृतिक जुड़ाव में संतुलन बनाया जाता है। प्रधानमंत्री अनवर इब्राहिम ने इस तरीके को अपनाने में काफी कुशलता दिखाई है।

जो विदेशी नेता या प्रतिनिधि हिंदी गाने गाते हैं या सीधे तौर पर भारतीय सांस्कृतिक चीजों से जुड़ते हैं, वे पब्लिक डिप्लोमेसी (जन-कूटनीति) के एक बहुत असरदार तरीके का इस्तेमाल करते हैं। आज के अंतरराष्ट्रीय संबंधों में, जहां प्रभाव राजनीतिक या सैन्य दबाव के बजाय आकर्षण पर टिका होता है, किसी देश की लोकप्रिय संस्कृति से सीधा जुड़ाव कूटनीतिक तनाव को कम करता है। इससे तुरंत सद्भावना बढ़ती है, हालांकि अगर यह दिखावा लगे तो बनावटी भी लग सकती है।

पारंपरिक कूटनीतिक प्रोटोकॉल औपचारिक रिक्रि्ट, राजकीय भोज और तय्युदा बयानों पर निर्भर करता है, जो अक्सर पक्षों के बीच दूरी बढ़ाते हैं। जब कोई विदेशी प्रतिनिधि कोई सांस्कृतिक काम करता है, जैसे कि कोई मशहूर

हिंदी गाना गाना, तो आम प्रोटोकॉल से हटकर किया गया यह काम अपनापन, विनम्रता और कोशिश को दिखाता है; लेकिन अगर इसे अच्छी तरह से नहीं लिया गया, तो इसके अजीब लगने का खतरा भी रहता है। इस संरचनात्मक बदलाव से कई तरह से यह बदलता है कि राजनयिक बातचीत को कैसे देखा जाता है—

सम्मान और तैयारी का संकेत- किसी विदेशी भाषा में गाने के बोल सीखना काफी मेहनत का काम है, जो यह दिखाता है कि आने वाला नेता मेज़बान देश की सांस्कृतिक पहचान को महत्व देता है।

राजनीतिक हस्तियों को मानवीय रूप देना यह तरीका किसी नेता के बारे में जनता की सोच का काम है, जो यह दिखाता है कि आने वाला नेता मेज़बान देश की सांस्कृतिक पहचान को महत्व देता है।

हिंदी सिनेमा (बॉलीवुड) और संगीत ऐतिहासिक रूप से वैश्विक सॉफ्ट पावर के बड़े माध्यम रहे हैं। दशकों से, भारतीय सिनेमा मध्य एशिया, मध्य पूर्व, अफ्रीका, पूर्वी यूरोप और दक्षिण-पूर्व एशिया में लोकप्रिय रहा है।

जब गैर-भारतीय नेता शास्त्रीय या आधुनिक हिंदी गाने गाते हैं, तो वे लोगों की पुरानी सांस्कृतिक यादों को ताज़ा करते हैं— जैसे सोवियत-बाद के देशों और रूस में, सर पे लाल टोपी रूसी गाना, जिसे मेरा जूता है जापानी के नाम से भी जाना जाता है, 1955 की बॉलीवुड क्लासिक फ़िल्म श्री 420, जिसमें राज कपूर मुख्य भूमिका में थे, को बहुत ज्यादा लोकप्रियता मिली। इस वापसी ने सोवियत-युग की यादें ताज़ा कर दीं और शीत युद्ध के बाद के रिश्तों को फिर से मज़बूत किया, जिससे राज कपूर एक सांस्कृतिक आइकन के तौर पर उभरे। दक्षिण-पूर्व एशिया में, रामायण और महाभारत जैसे साझा महाकाव्य और बॉलीवुड संगीत, गहरी सांस्कृतिक और भाषाई जड़ों वाले रिश्तों को और मज़बूत करते हैं।

पंडथमी देशों में, जिनमें अमेरिका और ब्रिटेन शामिल हैं, आज के दौर के ग्लोबल हिट गाने और क्रॉसओवर ट्रैक प्रभावशाली भारतीय समुदाय और वहाँ के मसदाताओं से जुड़ते हैं। भारतीय जनता और प्रवासी समुदायों से सीधा जुड़ाव: सरकार के मंत्रियों तक सीमित पारंपरिक विदेश नीति की पहलों के उलट, सांस्कृतिक जुड़ाव की कोशिशें

विश्व हृदय दिवस



अवॉयड करना चाहिए इसीलिए विश्व हृदय दिवस का उद्देश्य लोगों को हर साल हार्ट से संबंधित बीमारियों के प्रति जागरूकता करना है। सबसे पहले विश्व स्वास्थ्य संगठन यानि कि WHO ने दुनिया में तेज़ी से बढ़ रहे हार्ट के मरीजों के बढ़ते हुए मामलों को देखकर विश्व हृदय दिवस मनवा जाने का प्रस्ताव रखा था। वर्ष 2000 में विश्व स्वास्थ्य संगठन ने पहली बार दुनिया के सामने विश्व हृदय दिवस को मनाए जाने की घोषणा की थी। जिसके बाद से हर साल सितंबर माह के आखिरी रविवार को मनाया जाने लगा और वर्ष 2014 से इसकी एक तारीख निश्चित कर दी गयी जिससे कि विश्व हृदय दिवस 29 सितंबर को मनाया जाने लगा। इस दिन को मनाने का एकमात्र उद्देश्य है हृदय से जुड़ी समस्याओं को कम करने के लिए लोगों में

जागरूकता फैलाना। इस दिन हर साल कई देशों में कार्यक्रमों का आयोजन करके लोगों को स्वस्थ हृदय के प्रति जागरूक किया जाता है। आज के समय में दिन-प्रतिदिन हृदय रोगियों की संख्या बहुत तेजी से बढ़ रही है। इसके साथ ही हृदय संबंधी बीमारियाँ जिसमें हार्ट अटैक सबसे ज्यादा आइकन के तौर पर उभरे। दक्षिण-पूर्व एशिया में, कारण कई लोगों की असमय मृत्यु तक हो रही है। एक रिसर्च के अनुसार कम उम्र के लोगों में भी हृदय संबंधी समस्याएं सामने आ रही हैं और ये काफी चिंताजनक है क्योंकि पहले हृदय सम्बन्धी बीमारियाँ केवल बुजुर्गों और धूम्रपान करने वालों में पायी जाती थी। ऐसे में विश्व हृदय दिवस के माध्यम से लोगों को हृदय रोग के खतरे को कम करने के लिए प्रेरित और जागरूक करना बहुत आवश्यक है।

कैसे रखें अपने हृदय का ख्याल ?

- रोजाना नियमित रूप से व्यायाम और एक्सरसाइज करें।
- अपने खाने का विशेष ध्यान रखें, संतुलित और पौष्टिक आहार लें, फास्टफूड और तला-भूना खाने से बचे, खाने में नमक की मात्रा कम रखें और अपनी डाइट में हरी सब्बियों और मौसमी फलों को शामिल करें।
- किसी भी तरह का तनाव या डेंशन ना लें और अगर ऐसा हो तो योग का सहारा लें।
- धूम्रपान का सेवन बिल्कुल ना करें क्योंकि ये हृदय सम्बन्धी बीमारियों के साथ-साथ कई अन्य बीमारियों का भी कारण है।
- एक अच्छे और स्वस्थ जीवन के लिए भरपूर और पर्याप्त नींद लें।

अमेरिका-चीन शायद टकराव से नियंत्रित प्रतिस्पर्धा की ओर

आनंद कुमार

अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप व चीनी राष्ट्रपति शी जिनपिंग की मुलाकात ने कूटनीतिक गर्मजोशी और रणनीतिक प्रतिस्पर्धा के बीच मौजूद विरोधाभास को एक बार फिर सामने ला दिया है। जिनपिंग के स्वागत के लिए जिस तरह की भव्य तैयारियाँ की गईं, उसने दुनिया का ध्यान खींचा। ट्रंप खुद उनकी अगुवानी करने पहुंचे। उन्होंने यह संदेश देने की कोशिश की कि दोनों देशों के बीच संबंधों को अमेरिका गंभीरता से लेता है। पर, वास्तविकता कहीं अधिक जटिल है। शिखर वार्ता से दोनों देशों के बीच चल रहे मूलभूत विवादों का कोई बड़ा समाधान सामने नहीं आया।

बैठक में शी जिनपिंग ने अमेरिका और चीन को प्रतिद्वंद्वी के बजाय साझेदार बनाने की जरूरत पर जोर दिया। उन्होंने कहा कि चीन का राष्ट्रीय पुनरुत्थान और ट्रंप का ‘मेक अमेरिका ग्रेट अगेन’ (मागा) अभियान एक-दूसरे के विरोधी नहीं हैं। यह बयान दोनों देशों के बीच टकराव को सीमित रखने की इच्छा को दर्शाता है। शिखर वार्ता में दोनों देशों ने व्यापार युद्ध में जारी विराम को आगे बढ़ाने पर सहमति जताई। इससे तत्काल आर्थिक तनाव कम करने में मदद मिल सकती है, पर इसे स्थायी समझौता मानना जल्दबाजी होगी। दोनों पक्षों की बीच टैरिफ, अमेरिकी कृषि उत्पादों के लिए पक्षों के खरीद, दुर्लभ खनिजों की आपूर्ति, तकनीकी प्रतिबंध, औद्योगिक सब्सिडी और चीन की अतिरिक्त उत्पादन क्षमता जैसे मुद्दे बने हुए हैं।

अमेरिका चाहता है कि चीन अमेरिकी कृषि उत्पादों की खरीद बढ़ाए और दुर्लभ खनिजों की आपूर्ति अधिक भरोसेमंद बनाए। दूसरी ओर, चीन के पास महत्वपूर्ण खनिजों और वैश्विक आपूर्ति शृंखलाओं में अपनी मजबूत स्थिति के कारण आर्थिक दबाव का एक महत्वपूर्ण साधन मौजूद है। इसलिए, व्यापार समझौते को किसी नए अमेरिका-चीन आर्थिक युग की शुरुआत के रूप में देखना उचित नहीं होगा। अमेरिका की कंपनियों को स्थिर



और अनुमानित कारोबारी वातावरण की जरूरत है, जबकि चीन भी बड़े वैश्विक बाजारों और अमेरिकी तकनीक तक पहुंच को महत्व देता है। ऐसे में, व्यापार युद्ध को दोबारा भड़कने से रोकना दोनों के हित में है। साथ ही, शी ने अमेरिका से ताइवान के प्रश्न पर सावधानी बरतने और ताइवान की स्वतंत्रता का विरोध करने का आग्रह किया। चीन ताइवान को अपने राष्ट्रीय हित का केंद्रीय मुद्दा मानता है, जबकि अमेरिका की ताइवान के प्रति लंबे समय से सुरक्षा प्रतिबद्धताएं रही हैं। इसी कारण, ताइवान को अमेरिकी हथियारों की प्रस्तावित करीब 14 अरब डॉलर की बिक्री भी दोनों देशों के बीच विवाद का विषय बन गई है। इस मुद्दे पर किसी निर्णायक समझौते का न होना दिखाता है कि व्यक्तिगत संबंधों और कूटनीतिक गर्मजोशी की भी अपनी सीमाएं हैं।

शी जिनपिंग द्वारा ‘थ्यूसीडाइड्स ट्रैप’ का उल्लेख भी ध्यान देने योग्य है। यह अवधारणा उस खतरे की ओर संकेत करती है, जिसमें किसी उभरती शक्ति और मौजूदा प्रमुख शक्ति के बीच प्रतिस्पर्धा अंततः संघर्ष का रूप ले सकती है। शी ने कहा कि ऐसे खतरे से बचने के लिए सहयोग, नियमित सैन्य संवाद तथा संकट को नियंत्रित करने वाले तंत्र विकसित करने की जरूरत है। इससे पता चलता है कि बीजिंग अमेरिका-चीन रणनीतिक प्रतिस्पर्धा के सैन्य टकराव

में बदलने के खतरे को समझता है। लेकिन, इस अवधारणा का उल्लेख यह भी बताता है कि दोनों देशों के बीच प्रतिस्पर्धा कितनी गहरी हो चुकी है। एआई अब इस प्रतिस्पर्धा का नया और जरूरी क्षेत्र बन चुका है। हालांकि, एआई को लेकर दोनों देशों का दृष्टिकोण अलग है। ट्रंप ने एआई के विकास में अत्यधिक नियमन से बचने की इच्छा दिखाई, जबकि शी ने एआई को मानव नियंत्रण में रखने और उसका उपयोग सामाजिक हितों के लिए करने पर जोर दिया।

अमेरिकी प्रौद्योगिकी क्षेत्र के प्रमुख लोगों की मौजूदगी ने भी स्पष्ट किया कि तकनीकी प्रतिस्पर्धा अब भू-राजनीतिक प्रतिस्पर्धा का हिस्सा बन चुकी है।

इस पूरी बैठक में एक दिलचस्प विरोधाभास दिखाई देता है। अमेरिका और चीन एक-दूसरे के लिए जरूरी भी हैं और एक-दूसरे के प्रतिस्पर्धी भी। दोनों को व्यापार, वैश्विक आर्थिक स्थिरता, एआई, संकट प्रबंधन और कई अंतरराष्ट्रीय मुद्दों पर सहयोग की जरूरत है। पर, कई मुद्दों पर दोनों के बीच गहरे मतभेद भी हैं। ऐसे में, संवाद का उद्देश्य अब प्रतिस्पर्धा को समाप्त करना नहीं, बल्कि उसे नियंत्रित करना दिखाई देता है। शी के स्वागत में दिखाई भव्यता को कुछ आलोचकों ने ‘डिप्लोमेनेंट’, यानी कूटनीति व प्रदर्शन का मिश्रण बताया। यह आलोचना पूरी तरह निराधार भी नहीं है। ट्रंप का व्यक्तिगत रूप से शी का स्वागत करना, सैन्य सम्मान और व्हाइट हाउस में भव्य कार्यक्रम निश्चित रूप से प्रतीकात्मक महत्व रखते हैं। कूटनीति में प्रतीकों और व्यक्तिगत संबंधों की अपनी भूमिका होती है। वे कठिन बातचीत के लिए वातावरण तैयार कर सकते हैं। पर, केवल इससे ही मतभेदों का समाधान नहीं हो सकता। असली सफलता इससे तय होगी कि दोनों

देश अपने मतभेदों को नियंत्रित करने के लिए कितने प्रभावी तंत्र बना पाते हैं। दुनिया के दूसरे देशों के लिए भी इस बैठक का महत्व काफी है। यदि अमेरिका-चीन के बीच तनाव बढ़ता है, तो वैश्विक अर्थव्यवस्था में अनिश्चितता बढ़ेगी और हिंद-प्रशांत के देशों के रणनीतिक विकल्प भी अधिक जटिल होंगे। इसके विपरीत, यदि दोनों देश प्रतिस्पर्धा को नियंत्रित करने में सफल होते हैं, तो कुछ हद तक स्थिरता का वातावरण बन सकता है।

भारत के लिए यह स्थिति विशेष रूप से महत्वपूर्ण है। भारत के अमेरिका के साथ तेजी से मजबूत होते रणनीतिक संबंध हैं, पर चीन के साथ भी उसका एक जटिल और महत्वपूर्ण संबंध है। यदि वाशिंगटन व बीजिंग अपने संबंधों में लंबे समय के लिए संवाद और प्रतिस्पर्धा के प्रबंधन का रास्ता अपनाते हैं, तो भारत को भी अपनी रणनीतिक गणनाओं को उसी के अनुरूप ढालना होगा। हिंद-प्रशांत, प्रौद्योगिकी सहयोग, आपूर्ति शृंखलाओं और क्षेत्रीय शक्ति संतुलन पर इसका प्रभाव पड़ सकता है। भारत के लिए चुनौती यह होगी कि वह अमेरिका के साथ अपनी रणनीतिक साझेदारी को मजबूत रखते हुए चीन के साथ अपने संबंधों का प्रबंधन भी प्रभावी ढंग से करे। ट्रंप-शी शिखर वार्ता का वास्तविक महत्व इस प्रयास में है कि अमेरिका और चीन अपनी प्रतिस्पर्धा को अनियंत्रित टकराव में बदलने से रोकने के लिए संवाद से रास्ते खुले रखें।

वाशिंगटन से निकला सबसे महत्वपूर्ण संदेश यही है कि अमेरिका व चीन शायद टकराव से नियंत्रित प्रतिस्पर्धा की ओर बढ़ रहे हैं, पर रणनीतिक प्रतिद्वंद्विता से आगे नहीं निकले हैं। ट्रंप और शी के बीच दिखी गर्मजोशी कुछ समय के लिए तनाव को कम तो कर सकती है, पर स्थायी स्थिरता इस बात पर निर्भर करेगी कि दोनों देश उन कठिन सवालों का समाधान कैसे खोजते हैं, जिन्हें कोई भी समारोह और कोई भी लाल कालीन नहीं ढक सकता, यानी व्यापार, तकनीक, ताइवान, सैन्य प्रतिस्पर्धा और बदलता वैश्विक शक्ति संतुलन।

आज का इतिहास

- 1650 इंग्लैंड में पहले मैरिज ब्यूरो की शुरुआत हुई थी।
- 1789 अमेरिका के युद्ध विभाग ने स्थायी सेना स्थापित की थी।
- 1836 मद्रास चैंबर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री की स्थापना हुई थी।
- 1855 फिलीपीन बंदरगाह स्पेनिश प्रशासन द्वारा विश्व व्यापार के लिए खोला गया था।
- 1864 चाफिन के फार्म की लड़ाई लड़ी गई थी।
- 1885 दुनिया में पहला सार्वजनिक इलेक्ट्रिक ट्रामवे ब्लैक पूल, इंग्लैंड में खोला गया था।
- 1911 इटली ने ऑटोमन साम्राज्य के ख़्वालाफ़ युद्ध की घोषणा की थी।
- 1915 टेलीफोन से पहला अंतरमहाद्वीपीय संदेश भेजा गया था।
- 1927 अमेरिका और मैक्सिको के बीच टेलीफोन सेवा की शुरुआत हुई थी।
- 1954 परमाणु अनुसंधान के लिए यूरोपीय संगठन की स्थापना पर हस्ताक्षर किए गए थे।
- 1959 भारत की आरती शाह तैरकर इंग्लिश चैनल पार करने वाली पहली एशियाई महिला बनीं।
- 1962 कोलकाता में बिड़ला तारा मंडल खुला था।
- 1971 बंगाल की खाड़ी में चक्रवातीय तूफान से करीब 10 हज़ार लोगों की मौत हुई थी।
- 1977 सोवियत संघ ने स्पेस स्टेशन साल्युत 6 को पृथ्वी की कक्षा में स्थापित किया था।
- 1978 पोप जॉन पॉल प्रथम की रहस्यमय हालात में मौत हो गई थी।
- 1988 नासा ने चैलेंजर आपदा के बाद पहला मिशन एसटीएस-26 लॉन्च किया था।
- 1990 वाशिंगटन नेशनल कैथेड्रल का निर्माण पूरा हुआ था।
- 2000 चीन की मुन्चोनाक कोयला खान में 100 लोगों की मृत्यु हो गयी थी।
- 2002 बसान में 14वें एशियाई खेलों का उद्घाटन हुआ था।
- 2003 ईरान ने यूरेनियम परिशोधन कार्यक्रम जारी रखने का निर्णय लिया था।
- 2006 विश्व की पहली महिला अंतरिक्ष पर्यटक ईरानी मूल की अमेरिका नागरिक अनुशेह अंसारी पृथ्वी पर सकुशल लौटी थीं।
- 2009 अंतर्राष्ट्रीय मुक़ेबाज़ी फ़ेडरेशन की ताज़ा रैंकिंग में बिजेन्द्र को 75 किग्रा0 में 2700 अंकों के साथ में पहला स्थान दिया गया था।
- 2011 चीन ने जिकान उपग्रह प्रक्षेपण केन्द्र से पहली अंतरिक्ष प्रयोगशाला तियांगोंग-1 को अंतरिक्ष की कक्षा में सफलतापूर्वक स्थापित किया था।

कितना जायज हैं चुनाव आयोग की कार्यप्रणाली पर कांग्रेस के सवाल

मनोज कुमार अग्रवाल

आम जन की समस्याओं से विमुख विपक्ष इस बार चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार के खिलाफ मुखर हो उठा है। लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी ने एसआईआर प्रक्रिया को संस्थागत चोरी करार देते हुए आरोप लगाया कि चुनाव आयोग गरीबों के वोट काटने के लिए सत्ता पक्ष के साथ खुलकर मिला हुआ है।इन मुद्दों को लेकर कांग्रेस ने देश के अलग-अलग हिस्सों और राज्यों में चुनाव आयोग के दफ्तरों के बाहर देशव्यापी प्रदर्शन व विरोध-प्रदर्शन करने की घोषणा की है।

उधर चुनाव आयोग ने अपने ऊपर लगे इन तमाम आरोपों और आंतरिक कलह की खबरों को खारिज किया है। आयोग का कहना है कि प्रशासनिक बैठकों में अलग-अलग नोट्स और सुझाव दर्ज होना एक सामान्य और नियमित प्रक्रिया है। आयोग के अनुसार, एसआईआर और अन्य सभी चुनावी फैसले पूरी सहमति व कानूनी प्रावधानों के तहत ही लिए गए हैं।

आपको बता दें कि हाल ही में एक अंग्रेजी दैनिक की खबर में दावा किया गया था कि निर्वाचन आयुक्त सुखबीर सिंह और विपक्ष के अनुभार, मौजूदा संवैधानिक सूची के एसआईआर के दौरान नाम जोड़े और हटाए जाने समेत कई मुद्दों पर आपत्तियां जताई थीं। रिपोर्ट के अनुसार, संधू और जोशी ने पिछले 10 महीनों में कम से कम 14 बार लिखित रूप से आपत्तियां दर्ज कीं। इनमें से चार आपत्तियां एक ही दिन में उन फैसलों

और आदेशों को लेकर दर्ज की गईं, जिनकी जानकारी उन्हें नहीं थी। विवाद के बीच, निर्वाचन आयोग ने एक बयान में कहा, आयोग के सभी आधिकारिक आदेश, निर्णय पूर्ण कानूनी मान्यता प्राप्त हैं। किसी भी संस्थान में अलग-अलग विचार और टिप्पणियां विचार-विमर्श का सामान्य हिस्सा हैं। तीनों आयुक्त ही नहीं, बल्कि आयोग का प्रत्येक अधिकारी चुनाव प्रणाली में सुधार के लिए अपने सुझाव देने के लिए पूरी तरह अधिकृत है।

यहां गौरतलब है कि मतदाता सूचियों को दुरुस्त करने के लिए चुनाव आयोग द्वारा चलाए जा रहे एसआईआर के तहत अब तक 30 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों की मसौदा मतदाता सूचियों से 13 करोड़ से अधिक मतदाताओं के नाम हटा दिए गए हैं। इसकी शुरुआत जून 2025 में बिहार से हुई थी। इस दौरान चुनाव आयोग ने चार राज्यों और एक केंद्र शासित प्रदेश में विधानसभा चुनाव भी कराए जिनमें बिहार, पश्चिम बंगाल, तमिलनाडु और केरल शामिल हैं। असम में विधानसभा चुनाव के लिए मतदाता सूचियों का एसआईआर नहीं कराया गया। एसआईआर को सर्वोच्च न्यायालय में भी चुनौती दी गई है।

आपको पता रहे कि कांग्रेस ने इस विवाद को ज्ञानेशगेट करार दिया जबकि मतदाता बनर्जी के नेतृत्व वाली तुणमूल कांग्रेस के विभिन्न धड़ों ने मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार के महाभियोग और एसआईआर से पहले मौजूद मतदाता सूची के आधार पर पश्चिम बंगाल में नए विधानसभा चुनाव कराने की मांग की। सत्तारूढ़



भाजपा ने चुनाव आयोग के भीतर मतभेदों को कमतर बताते हुए इसे शुद्ध लोकतंत्र का प्रतिबिंब बताया। लोकसभा में विपक्ष के नेता राहुल गांधी ने एक्स पर एक पोस्ट में आरोप लगाया कि भाजपा, आरएसएस और चुनाव आयोग ने वोट चोरी कर देशद्रोह किया है और न्याय होकर रहेगा। गांधी ने कहा कि वोट चोरी भारतीय जनता के खिलाफ अपराध और हमारे संविधान पर सीधा हमला है। कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने सवाल किया कि क्या राज्यसभा के सभापति अब 24 अप्रैल को 73 विपक्षी सांसदों द्वारा मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार को हटाने की मांग को लेकर दिए गए नोटिस पर फैसला करेंगे। उन्होंने कहा कि मानसून सत्र को अभी तक अनिश्चितकाल के लिए स्थगित नहीं किया गया है।

इधर इस मुद्दे पर भाजपा का भी वर्जन आया है। पार्टी प्रवक्ता संबित पात्रा ने कहा है कि आधिकारिक विचार-विमर्श के दौरान चुनाव आयुक्तों द्वारा अलग-अलग मत व्यक्त किए जाने संबंधी मीडिया रिपोर्ट शुद्ध

लोकतंत्र को दर्शाती है। उन्होंने कहा कि यदि चुनाव आयुक्त आपस में संवाद और विचारों का आदान प्रदान नहीं करते तो विपक्षी दल उन पर सरकार की हां में हां मिलाने का आरोप लगाते। निर्वाचन आयोग के कामकाज को नियंत्रित करने वाला कानून स्पष्ट रूप से कहता है कि उसके फैसले सर्वसम्मति से या बहुमत से होने चाहिए। टीएन शेषन मामले (1995) में सुप्रीम कोर्ट की संविधान पीठ ने सामूहिक निर्णय लेने की व्यवस्था का समर्थन किया था। अदालत ने स्पष्ट किया था कि मुख्य निर्वाचन आयुक्त न तो सम्राट हैं और न ही अन्य निर्वाचन आयुक्तों से ऊपर कोई प्राधिकारी। वह आयोग के अध्यक्ष के रूप में कार्य करते हैं, लेकिन सभी सदस्यों के पास निर्णय लेने के समान अधिकार होते हैं।

चुनाव आयुक्तों में असहमति को लेकर इतना हंगामा लोकतांत्रिक दृष्टि से ठीक नहीं, क्योंकि लोकतंत्र में असहमति का विशेष महत्व है। संसद में सांसद एक-दूसरे के विचारों से असहमत होते हैं। इसी तरह विधानसभाओं और नगर निगमों से लेकर पंचायतों तक में विभिन्न मुद्दों पर हर माननीय की अपनी राय होती है। देश के सर्वोच्च न्यायालय में माननीय न्यायधीशों की अपनी अलग-अलग राय होती है। मुख्य चुनाव आयुक्त से संबंधित कानून को लेकर दो जजों की पीठ में मतभेद

परिसीमन की आहट के बीच आरक्षित राजनीति का सवाल

रुद्र प्रताप सिंह

देश में संभावित परिसीमन को लेकर राजनीतिक बहस तेज होने के साथ अनुसूचित जाति (स्छ) और अनुसूचित जनजाति (स्छज) के प्रतिनिधित्व का सवाल भी महत्वपूर्ण होता जा रहा है। परिसीमन केवल निर्वाचन क्षेत्रों की सीमाओं के पुनर्निर्धारण तक सीमित नहीं रहेगा, बल्कि आरक्षित सीटों के भूगोल और राजनीतिक प्रतिनिधित्व पर भी इसका असर पड़ सकता है। निर्वाचन आयोग के अनुसार, मौजूदा संवैधानिक व्यवस्था में लोकसभा और विधानसभा सीटों के पुनर्समायोजन से जुड़ी प्रक्रिया 2026 के बाद होने वाली पहली जनगणना के आंकड़ों से जुड़ी है। परिसीमन के साथ सबसे बड़ा सवाल केवल यह नहीं होगा कि स्छ/स्छज के लिए कितनी सीटें आरक्षित होती हैं, बल्कि यह भी होगा कि इन सीटों से किस तरह का नेतृत्व सामने आता है। आरक्षित सीटों की संख्या बढ़ना अपने आप में राजनीतिक सशक्तिकरण की गारंटी नहीं है। प्रतिनिधित्व का प्रभाव इस बात से भी जुड़ा है कि निर्वाचित प्रतिनिधि अपने क्षेत्र और समुदाय से जुड़े मुद्दों को नीति और राजनीतिक विमर्श में कितनी जगह दिलाते हैं। इसी संदर्भ में आरक्षित राजनीति में परिवारवाद और राजनीतिक विरासत की बहस भी सामने आती है। राजनीतिक परिवारों से आने वाले उम्मीदवारों को पहचान, संठाटनात्मक नेटवर्क और लंबे समय से बने राजनीतिक संपर्कों का लाभ मिल सकता है, जबकि गैर-राजनीतिक पृष्ठभूमि से आने वाले उम्मीदवारों को अपनी पहचान बनाने में अधिक समय लग सकता है। हालांकि, केवल राजनीतिक परिवार से आने के आधार पर किसी उम्मीदवार की योग्यता पर निष्कर्ष निकालना उचित नहीं होगा। वास्तविक सवाल उम्मीदवार चयन की प्रक्रिया, जमीनी काम और राजनीतिक दलों के भीतर उपलब्ध अवसरों का है। परिसीमन के बाद निर्वाचन क्षेत्रों की सीमाएं और आरक्षण की स्थिति बदल सकती है। निर्वाचन आयोग के अनुसार, परिसीमन आयोग निर्वाचन क्षेत्रों की सीमाओं के पुनर्निर्धारण

का काम करता है और उसके आदेशों को कानून का प्रभाव प्राप्त होता है। ऐसे में किसी क्षेत्र का सामान्य से आरक्षित या आरक्षित से सामान्य सीट में बदलना स्थानीय राजनीतिक समीकरणों को प्रभावित कर सकता है। इसका असर अलग-अलग राज्यों और क्षेत्रों में अलग-अलग हो सकता है। आरक्षित राजनीति के भीतर भी प्रतिनिधित्व की बहस महत्वपूर्ण है। 1 अगस्त 2024 को सुप्रीम कोर्ट की सात न्यायाधीशों की संविधान पीठ ने अनुसूचित जातियों के भीतर उप-वर्गीकरण को संवैधानिक व्यवस्था के दायरे में स्वीकार्य माना। यह फैसला चुनावी सीटों के आरक्षण से सीधे जुड़ा हुआ नहीं है, लेकिन स्छ समुदायों के भीतर लाभ के वितरण और अपेक्षाकृत अधिक वॉचत समूहों की हिस्सेदारी पर बहस के लिए महत्वपूर्ण है। अब सवाल राजनीतिक दलों की टिकट वितरण प्रक्रिया पर भी है। क्या लंबे समय से संगठन में काम कर रहे कार्यकर्ताओं, सामाजिक रूप से सक्रिय युवाओं, महिलाओं और अलग-अलग स्छ/स्छज समुदायों से आने वाले चेहरों को पर्याप्त अवसर मिलता है? क्या उम्मीदवार चयन में जमीनी काम और स्थानीय स्वीकार्यता को पर्याप्त महत्व दिया जाता है? इन सवालों का जवाब व्यापक चुनावी आंकड़ों और उम्मीदवारों की सामाजिक-राजनीतिक पृष्ठभूमि के अध्ययन से ही स्पष्ट हो सकता है। परिसीमन के बाद यदि आरक्षित सीटों का भूगोल बदलता है, तो यह नई राजनीतिक संभावनाएं भी पैदा कर सकता है। बहस केवल सीटों की संख्या तक सीमित रखने के बजाय इस बात पर होनी चाहिए कि बदलते राजनीतिक नक्शे में प्रतिनिधित्व कितना व्यापक और विविध होगा। लोकतंत्र में प्रतिनिधित्व का अर्थ केवल संसद या विधानसभा में सीट हासिल करना नहीं, बल्कि क्षेत्रीय और सामाजिक मुद्दों को प्रभावी ढंग से उठाना तथा मतदाताओं के प्रति जवाबदेही सुनिश्चित करना भी है। आखिरकार परिसीमन भारत के राजनीतिक नक्शे में बदलाव ला सकता है,

टकराव के बीच अमेरिका- चीन मिलन के कूटनीतिक समझौते

सौरभ वर्ण्य

विश्व राजनीति में अमेरिका और चीन के संबंध इस समय एक ऐसे दौर से गुजर रहे हैं, जहां टकराव और संवाद दोनों साथ-साथ दिखाई दे रहे हैं। एक ओर दोनों देश व्यापार, तकनीक, ताइवान, दुर्लभ खनिज, कृत्रिम बुद्धिमत्ता और वैश्विक प्रभाव के विस्तार को लेकर एक-दूसरे के सामने खड़े हैं, तो दूसरी ओर आर्थिक हित उन्हें बातचीत की मेज पर भी ला रहे हैं। यही विरोधाभास आज के बदलते वैश्विक शक्ति संतुलन का सबसे बड़ी तस्वीर है। अमेरिका और चीन की हालिया नजदीकी को केवल मित्रता के रूप में देखना जितना गलत होगा, उतना ही इसे महज दिखावटी कूटनीति मान लेना भी उचित नहीं होगा। वास्तविकता यह है कि दोनों महाशक्तियां यह सहमत रही हैं कि लगातार बढ़ता टकराव किसी एक पक्ष के हित में नहीं है। दुनिया की दो सबसे बड़ी अर्थव्यवस्थाओं के बीच व्यापारिक तनाव बढ़ने का असर केवल वाशिंगटन और बीजिंग तक सीमित नहीं रहता, बल्कि उसका प्रभाव पूरी वैश्विक अर्थव्यवस्था, आपूर्ति शृंखलाओं, निवेश और विकास की गति पर पड़ता है।

यही कारण है कि तीखे बयानों और रणनीतिक प्रतिस्पर्धा के बावजूद संवाद के दरवाजे खुले रखे जा रहे हैं। अमेरिका अपनी आर्थिक और तकनीकी बढ़त को सुरक्षित रखना चाहता है, जबकि चीन अपने औद्योगिक विस्तार, निर्यात बाजार और तकनीकी विकास के लिए स्थिर अंतरराष्ट्रीय वातावरण चाहता है। दोनों के हितों में टकराव है, लेकिन उनकी आर्थिक आवश्यकताएं उन्हें एक-दूसरे से पूरी तरह अलग होने की अनुमति नहीं देतीं। सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि आज अमेरिका और चीन की प्रतिस्पर्धा केवल व्यापार तक सीमित नहीं रह गई है। तकनीक इस संघर्ष का नया केंद्र बन चुकी है। कृत्रिम बुद्धिमत्ता, सेमीकंडक्टर, दूरसंचार, इलेक्ट्रिक वाहन, उन्नत विमान और दुर्लभ खनिज जैसे क्षेत्र अब आर्थिक विकास के साथ-साथ राष्ट्रीय सुरक्षा से भी जुड़े हुए हैं। अमेरिका चीन की तकनीकी क्षमता और औद्योगिक विस्तार को लेकर सतर्क है, वहीं चीन अमेरिकी तकनीकी प्रतिबंधों को अपने विकास के रास्ते में बाधा के रूप में देखता है। इसके बावजूद दोनों देशों के बीच बातचीत का



जारी रहना अपने आप में महत्वपूर्ण है। इसका अर्थ यह नहीं कि दोनों के बीच रणनीतिक अविश्वास समाप्त हो गया है। बल्कि इसका अर्थ यह है कि दोनों देश अपने मतभेदों को नियंत्रित रखने और उन क्षेत्रों में समझ बनाने की कोशिश कर रहे हैं जहां परस्पर हित जुड़े हुए हैं।

ताइवान का मुद्दा इस रिस्ते की सबसे संवेदनशील परीक्षा है। व्यापार और आर्थिक मामलों में समझ विकसित हो सकती है, लेकिन ताइवान को लेकर अमेरिका और चीन की रणनीतिक सोच में मूलभूत अंतर मौजूद है। इसी तरह दक्षिण चीन सागर, तकनीकी प्रतिस्पर्धा और वैश्विक प्रभाव के विस्तार को लेकर भी दोनों देशों के बीच मतभेद आसानी से समाप्त होने वाले नहीं हैं। इसलिए वर्तमान नजदीकी को स्थायी दोस्ती की शुरुआत मानना जल्दबाजी होगी।

असल में अमेरिका और चीन के संबंधों में एक नई तरह की कूटनीति दिखाई दे रही है। प्रतिस्पर्धा के साथ सह-अस्तित्व की कूटनीति। दोनों देश एक-दूसरे के प्रभाव को सीमित करना चाहते हैं, लेकिन पूर्ण टकराव से भी बचना चाहते हैं। वे व्यापार करना चाहते हैं, लेकिन रणनीतिक निर्भरता कम करना चाहते हैं। वे संवाद चाहते हैं, लेकिन अपनी राष्ट्रीय सुरक्षा और तकनीकी हितों से समझौता करने के लिए तैयार नहीं हैं।यही स्थिति आने वाले समय की विश्व राजनीति को भी प्रभावित करेगी। यदि अमेरिका और चीन के बीच व्यापारिक तनाव नियंत्रित रहता है तो वैश्विक बाजारों को कुछ स्थिरता मिल सकती है। इसके विपरीत यदि शुल्क युद्ध फिर तेज होता है तो उसका असर विकासशील देशों पर भी पड़ेगा। महंगाई, आपूर्ति शृंखला और निर्यात बाजारों में अस्थिरता बढ़

सकती है।

भारत के लिए इस बदलते समीकरण को समझना विशेष रूप से महत्वपूर्ण है। भारत अमेरिका के साथ रणनीतिक और आर्थिक संबंधों को आगे बढ़ा रहा है, वहीं चीन भारत का पड़ोसी और एक महत्वपूर्ण व्यापारिक साझेदार है। ऐसे में भारत के लिए किसी एक शक्ति-गुट का हिस्सा बनने के बजाय अपने राष्ट्रीय हितों के आधार पर संतुलित और स्वतंत्र विदेश नीति को आगे बढ़ाना अधिक महत्वपूर्ण हो जाता है।

अमेरिका और चीन के बीच यदि तनाव कम होता है तो भारत के लिए वैश्विक आर्थिक स्थिरता का वातावरण बन सकता है। वहीं यदि दोनों देशों के बीच प्रतिस्पर्धा बनी रहती है तो भारत के प्रतिनिधिनिर्माण, आपूर्ति शृंखला और निवेश के क्षेत्र में अवसर भी पैदा हो सकते हैं। लेकिन इन अवसरों को हासिल करने के लिए भारत को अपनी उत्पादन क्षमता, तकनीकी दक्षता और निर्यात प्रतिस्पर्धा को मजबूत करना होगा। सबसे बड़ा सवाल यह है कि अमेरिका और चीन की यह नजदीकी कितने समय तक टिकती है। क्या यह वास्तविक समझ की दिशा में कदम है या केवल तत्काल आर्थिक दबावों को कम करने की रणनीति? इसका उत्तर आने वाला समय देगा। दोनों देशों के बीच कई ऐसे मुद्दे हैं जिन पर सहमति बनना आसान नहीं है। इसलिए किसी एक बैठक या अस्थायी समझौते को स्थायी परिवर्तन का संकेत मानना उचित नहीं होगा।

फिर भी एक बात स्पष्ट है आज की दुनिया में महाशक्तियां भी एक-दूसरे से पूरी तरह कटकर नहीं चल सकतीं। आर्थिक परस्पर निर्भरता, वैश्विक व्यापार, तकनीकी विकास और साझा चुनौतियां उन्हें संवाद के लिए मजबूर करती हैं। यही कारण है कि अमेरिका और चीन के बीच टकराव के बावजूद बातचीत का सिलसिला जारी है।

अमेरिका और चीन की वर्तमान नजदीकी का सबसे बड़ा संदेश यही है कि विश्व राजनीति अब केवल शक्ति प्रदर्शन से नहीं, बल्कि शक्ति और आवश्यकता के संतुलन से संचालित हो रही है।दोनों देश प्रतिस्पर्धी हैं, लेकिन एक-दूसरे की आर्थिक और वैश्विक भूमिका को अंदर देखी नहीं कर सकते। इसलिए इस नजदीकी को दोस्ती या दुश्मनी के पुराने पैमाने पर देखने के बजाय बदलती विश्व व्यवस्था के संकेत के रूप में समझना चाहिए।



अधिकारी अपने क्षेत्राधिकार में उनकी पुष्टि करने का काम करेंगे। पोर्टल में अब उन्हें लॉगिन पासवर्ड का अधिकार मिलेगा, ताकि वह अपना काम पूरे अधिकार के साथ कर पाएं। अभी जो नोटिस भेजे जा रहे थे, वह कंप्यूटर के माध्यम से भेजे जा रहे थे। इस प्रक्रिया में भी बदलाव का निर्णय लिया गया है। फार्म 6 में जो अतिरिक्त प्रविष्टि जोड़ी गई थी।

अब उसके अनुसार माता-पिता, दादा-दादी के सत्यापन की जरूरत नहीं होगी। रीजनल इलेक्ट्रोरल अफसर का फैसला मान्य होगा केंद्रीय चुनाव आयोग ने पिछले कुछ वर्षों में जिस तरह से सॉफ्टवेयर के माध्यम से चुनाव को प्रभावित किया था। 30 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के 13.37 करोड़ मतदाताओं के नाम काटे गए थे। जब यह मामला खुला, तब चुनाव आयोग के साथ-साथ सरकार को भी पसीने आने लगे हैं। 13 करोड़ मतदाता यदि सड़कों पर आ जाएं, तो क्या स्थिति बनेगी, इसका अंदाजा आसानी से लगाया जा सकता है। इंडियन एक्सप्रेस की रिपोर्ट के बाद केंद्रीय चुनाव आयोग द्वारा जो मनमानी की जा रही थी। मतदाता सूची से लेकर मतदान और मतगणना मे जो गड़बड़ी दिल्ली में बैठे अधिकारियों द्वारा पोर्टल के माध्यम से की जा रही थी। वह पूरी तरह से उजागर हो चुकी है।

सारे देश में मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार के साथ-साथ, गृहमंत्री अमित शाह और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के इस्तीफा की मांग उठने लगी है। ऐसी स्थिति में इस विवाद को आगे बढ़ाने की जगह इसे ठंडा करने में केंद्रीय चुनाव आयोग के साथ-साथ अब सरकार भी सजग हो गई है जो नया केंद्रीय पोर्टल बनाया गया है, उसके ऑडिट की

का समाचार सुर्खियों में है। राजनीतिक दलों में विचारों को लेकर मतभेद के समाचार तो आये दिन समाचार पत्रों की सुर्खियां बनते हैं, इसके बाद जब निर्णय बहुमत से या सर्वसम्मति से लिया जाता है तो असहमति वाला पक्ष पर्दे के पीछे चला जाता है।

चुनाव आयुक्तों में असहमति एक स्वाभाविक व लोकतांत्रिक बात है। कानूनी की दृष्टि से भी हर आयुक्त को अपने विचार प्रकट करने का अधिकार है, लेकिन फैसला बहुमत या सर्वसम्मति से जो होता है वही मान्य होता है।

चुनाव आयुक्तों के आपसी मतभेद तब तक ही महत्व रखते हैं जब तक अंतिम निर्णय नहीं हो जाता है। निर्णय चाहे बहुमत से आये या सर्वसम्मति से मान्य तो वो ही होगा। विरोध के लिए विरोध लोकतंत्र के हित में नहीं। यह बात उन सबको समझनी चाहिए जो लोकतांत्रिक प्रणाली में विश्वास रखते हैं।

जाहिर है कि विपक्ष चुनाव आयोग को घेरने के लिए तमाम तिकड़म लगा रहा है। संभव है कि यह अखुबारी रिपोर्ट भी एक सुनियोजित ताने बाने का हिस्सा हो जिस तरह मामले को सनसनीखेज बना कर पेश किया गया है और हाथों हाथ नेता प्रतिपक्ष चुनाव आयुक्त पर आरोप लगा कर राजनीतिक दाढ़ पेच लगा रहे हैं वह खुद में संदेह भरा है। बहरहाल सरकार और चुनाव आयोग को इस सब पर प्रखर होकर अपना पक्ष रखना होगा वहीं चुनाव आयुक्तों के बीच अंदरूनी के खेमेबाजी को भी निगरानी की जरूरत है।

मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश का सरेंडर

बात दो चुनाव आयुक्त और विपक्ष द्वारा की जा रही है। ऐसी स्थिति में उसके आडिट के लिये कार्यवाही शुरू करने का निर्णय ले लिया गया है।

पिछले वर्षों में केंद्रीय चुनाव आयोग राजनीतिक दलों से चर्चा भी नहीं करता था। बड़े-बड़े बदलाव करने के बाद भी उसकी जानकारी विपक्षी दलों को नहीं देता था। बड़े पैमाने पर डिजिटल तकनीकी में, हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर के माध्यम से अलग-अलग प्रोग्राम बनाकर जिस तरह की गड़बड़ी हो रही थी। अब ऐसा करना संभव नहीं रहा, चुनाव आयोग को आम जनता का विश्वास हासिल हो। इसके लिए अब सजगता निष्पक्षता और पारिदर्शिता के साथ चुनाव आयोग को काम करना होगा। जिस तरह से जनता में चुनाव आयोग को लेकर अविश्वास बना है। इसे समय रहते दूर नहीं किया गया, तो अराजकता की स्थिति बन सकती है। 13 करोड़ मतदाताओं का नाम काटना और 18 वर्ष से ज्यादा उम्र के युवाओं का नाम मतदाता सूची में नहीं जोड़ने से अब यह बवाल बड़ा हो गया है। चुनाव आयोग के कामकाज में एक बड़े ऑपरेशन की जरूरत है। सरकार और चुनाव आयोग ने कभी नहीं सोचा था, इस तरह की स्थिति आ सकती है। अब सुप्रीम कोर्ट को लेकर भी तरह-तरह की चर्चाएं होने लगी हैं।

पिछले 15 महीनो से एसआईआर का मामला सुप्रीम कोर्ट में चल रहा है। इसी बीच बिहार और पश्चिम बंगाल के चुनाव हो गए। चुनाव परिणामों ने सभी को आश्चर्यचकित किया हैं। सुप्रीम कोर्ट ने इतनी लंबी सुनवाई के बाद भी जब सारे मामले उसके सामने गए थे। उस समय कोई निर्णय न देकर एक तरह से केंद्रीय चुनाव आयोग को आंख बंद करके समर्थन किया था। सुप्रीम कोर्ट ने यहां तक कह दिया था कि इस बार वोट नहीं दे पाओगे, तो बाद में दे देना। सुप्रीम कोर्ट ने अपने विशेष अधिकार का प्रयोग करते हुए न्यायिक अधिकारियों को एसआईआर के काम में लगा दिया। जिसके कारण न्याय पालिका भी चुनाव आयोग के साथ-साथ कटघरे में खड़ी हो गई है। न्यायपालिका के लिए भी यह सबसे बड़ी चुनौती का समय है। संविधान प्रदत्त नागरिक अधिकारों को जिस तरह खत्म किया गया। उसको लेकर अब सारे देश में बवाल हो रहा है।

फरक्का से आगे बढ़कर गंगा बेसिन को देखने की जरूरत

कुमार कृष्ण

भारत-बांग्लादेश गंगा जल संधि और फरक्का बैराज को लेकर बिहार की चिंता केवल पानी के बंटवारे तक सीमित नहीं है। इसके साथ बाढ़, गाद, सिंचाई, नौवहन, पर्यावरण और राज्य के दीर्घकालिक जल अधिकार भी जुड़े हैं। दिसंबर 2026 में 1996 की भारत-बांग्लादेश गंगा जल साझा संधि की 30 वर्ष की अवधि पूरी होने के मद्देनजर पटना में आयोजित एकदिवसीय परिचर्चा में वक्ताओं ने बिहार की जल नीति को फरक्का बैराज से आगे बढ़ाकर पूरे गंगा बेसिन और नेपाल से आने वाली नदियों के समग्र संदर्भ में देखने की जरूरत बताई। बाबू जगजीवन राम शोध संस्थान, पटना में ‘बिहार पॉलिसी डायलॉग’ के बैनर तले आयोजित परिचर्चा के संयोजक प्रो. सुबोध कुमार थे। परिचर्चा में पूर्व विधानसभा अध्यक्ष उदय नारायण चौधरी, राजद के प्रदेश अध्यक्ष मंगनी लाल मंडल, जल विशेषज्ञ नीलय उपाध्याय, बक्सर के सांसद सुधाकर सिंह, एनआईटी पटना के पूर्व प्राचार्य ई. संतोष शिव, राजद नेता शाश्वत गौतम और पद्मश्री प्रो. रविंद्र सिन्हा सहित जल एवं गंगा बेसिन से जुड़े विशेषज्ञ मौजूद रहे। परिचर्चा का केंद्रीय सवाल था—क्या बिहार को बाढ़ और जल संकट का समाधान केवल फरक्का बैराज को हटाने में खोजा जा सकता है? वक्ताओं के बीच इस बात पर जोर रहा कि फरक्का को बिहार की बाढ़ का अकेला कारण मानना समस्या की जटिलता को सीमित कर देना होगा। बिहार के लिए हिमालय, नेपाल, उत्तर बिहार की सहायक नदियों और गंगा की मुख्यधारा को जोड़कर एक व्यापक जल नीति की जरूरत है। परिचर्चा में बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री लालू प्रसाद यादव और जल संसाधन विभाग द्वारा तत्कालीन मंत्री जगदानंद सिंह के मार्गदर्शन में तैयार किए गए 64 पृष्ठों के दस्तावेज का भी संदर्भ आया। इस दस्तावेज में गंगा में घटती जल उपलब्धता, अंतरराष्ट्रीय जल उपयोग, भारत-बांग्लादेश गंगा जल संधि और बिहार

के हितों से जुड़े अध्ययन एवं पत्राचार संकलित किए गए थे। वक्ताओं का कहना था कि करीब तीन दशक बाद जब गंगा जल संधि की समीक्षा का समय सामने है, तब पुराने दस्तावेजों को केवल अभिलेखागार में रखने के बजाय उनकी रोशनी में वर्तमान जल परिस्थितियों का पुनर्मूल्यांकन किया जाना चाहिए। बिहार की स्थिति इसलिए भी अलग है कि राज्य गंगा की मुख्यधारा के साथ-साथ गंडक, कोसी, घाघरा, महानंदा और सोन जैसी नदियों के जल तंत्र से प्रभावित होता है। नेपाल के हिमालयी जलग्रहण क्षेत्रों से आने वाला जल मानसून में बिहार के लिए बाढ़ का कारण बन सकता है, जबकि शुष्क मौसम में यही जल उपलब्धता सिंचाई, पेयजल और पारिस्थितिकी के लिए महत्वपूर्ण हो जाती है। परिचर्चा में 24 जनवरी 1997 को नई दिल्ली में हुई सचिव-स्तरीय बैठक का विशेष उल्लेख किया गया। बैठक में बिहार सरकार, केंद्रीय जल आयोग और गंगा बाढ़ नियंत्रण आयोग के अधिकारी शामिल थे। बैठक की कार्यवाही में बिहार के अधिकारियों की यह आपत्ति दर्ज है कि भारत-बांग्लादेश गंगा जल संधि को अंतिम रूप देने से पहले बिहार से परामर्श नहीं किया गया था और संधि के संभावित प्रभावों को लेकर राज्य ने चिंता जताई थी। बैठक में गंगा जल उपयोग के प्रश्न पर गंगा बेसिन के आठ राज्यों को शामिल करने की आवश्यकता का भी उल्लेख किया गया था। यह दस्तावेज इसलिए महत्वपूर्ण है कि इससे यह सवाल सामने आता है कि अंतरराष्ट्रीय स्तर पर जल समझौते केंद्र सरकार के अधिकार क्षेत्र में होने के बावजूद उनके प्रभावों से प्रभावित राज्यों की भागीदारी किस रूप में सुनिश्चित की जाए। 1996 की संधि में भारत और बांग्लादेश के बीच फरक्का पर गंगा के जल प्रवाह के बंटवारे की व्यवस्था की गई थी। एक मार्च से दस मई के बीच दस-दिन के चक्रों में दोनों देशों के लिए जल उपलब्धता की व्यवस्था संधि का महत्वपूर्ण हिस्सा है।



ये है दुनिया का दूसरा सबसे बड़ा जंगल

यहां हमेशा होती रहती है बारिश

अपनी धरती पर बड़े-बड़े जंगल हैं, जहां हजारों तरह के पेड़-पौधे हैं और हजारों तरह के जीव रहते हैं। ऐसा ही एक घना जंगल है अफ्रीका महादेश के मध्य में। कांगो देश से जुड़ा यह जंगल दुनिया का दूसरा सबसे बड़ा जंगल है। इस जंगल में हमेशा बारिश होती रहती है, इस कारण इसे कांगो रेन फॉरेस्ट कहा जाता है।

- कांगो रेन फॉरेस्ट मध्य अफ्रीका में स्थित है। यह 23 लाख 45 हजार वर्ग किलोमीटर से भी अधिक क्षेत्र में फैला है। अपना देश भारत लगभग 32 लाख 87 हजार वर्ग किलोमीटर में फैला है। यानी अपने देश के लगभग 75 प्रतिशत क्षेत्र के बराबर है यह जंगल।
- यह रेन फॉरेस्ट दुनिया का दूसरा सबसे बड़ा जंगल है, जहां खूब बारिश होती है। यहां औसतन 58 इंच बारिश हर वर्ष होती है। पहले नम्बर पर अमेजन रेनफॉरेस्ट है, जो 55 लाख वर्ग किलोमीटर में है। यानी अपने देश के क्षेत्रफल से डेढ़ गुना ज्यादा क्षेत्र में है अमेजन का जंगल।
- कांगो रेन फॉरेस्ट का ज्यादा हिस्सा कांगो देश में आता है, जो अफ्रीका महादेश के मध्य में स्थित है। इसे डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ऑफ कांगो कहा जाता है। संक्षेप में इस देश को डीआरसी भी कहा जाता है और डीआर कांगो भी।
- इस घने जंगल का काफी हिस्सा ऐसा है, जहां अब तक इंसान नहीं पहुंच पाया है। यहां तक कि इस

- जंगल में रहने वाले लोग भी काफी बड़े हिस्से तक नहीं पहुंच पाए हैं। इन घने हिस्सों में सूर्य की एक प्रतिशत रोशनी ही जमीन तक पहुंच पाती है।
- इस जंगल में रहने वाले लोगों को पिग्मी कहा जाता है। यहां के पुरुषों की औसत लंबाई 4 फीट 10 इंच होती है, जबकि महिलाओं की औसत लंबाई 4 फीट 1 इंच होती है।
- इस जंगल में पांच नेशनल पार्क हैं, जिन्हें यूएन विश्व धरोहर का दर्जा प्राप्त है। यानी यह जंगल दुनिया भर के लिए बहुत महत्व रखता है।
- इस जंगल के बीच से कांगो नदी निकलती है, जिसकी लंबाई 4700 किलोमीटर है। यह नदी कांगो देश के अलावा कई और देशों से होकर गुजरती है। इसे



चीनू और पोपू की शरारत

चीनू और पोपू चौथी क्लास में पढ़ते थे, लेकिन थे अबल दर्जे के शरारती। ये दोनों कहीं पर भी कोई शरारत का मौका नहीं छोड़ते थे। अगर कोई उन्हें कहीं जाने का सीधा रास्ता पूछता तो वे उसे उल्टा रास्ता बता देते। अगर कोई फल वाला गुजरता तो वे उसे बातों में लगाकर उसके फल गायब कर देते। अपनी क्लास में भी वे खूब शरारत करते थे।

एक दिन रिवकू क्लास में यूनीफॉर्म की काले रंग की नई

पेंट पहनकर आया और चीनू को शरारत सूझी। वह पोपू से बोला- ‘आज रिवकू की पेंट ढीली करते हैं। आज यह नई पेंट पहनकर बहुत स्मार्ट समझ रहा है अपने आपको।’ पोपू बोला- ‘तो क्या करना है?’ चीनू ने कहा- ‘देखते जाओ मैं क्या करता हूं।’ रिवकू इंटरवल के समय अपनी सीट से उठकर कहीं बाहर गया हुआ था कि मौका देखते ही चीनू ने एक चॉक से उसकी सीट पर ‘शरारती रिवकू’ लिख दिया। यह कुछ इस तरह उल्टे अक्षरों में लिखा कि



छपकर सीधा लगे। इंटरवल खत्म होने के बाद सभी बच्चे अपनी-अपनी सीटों पर बैठ गये। रिवकू भी अपनी सीट पर आकर बैठ गया। क्लास टीचर ने ब्लैक बोर्ड पर कुछ लिखवाने के लिए रिवकू को बुलाया। रिवकू बड़े आराम से मुस्कराहट के साथ जब ब्लैक बोर्ड पर टीचर की बताई हुई बात लिखने लगा तो उसकी पेंट के पीछे ‘शरारती रिवकू’ छपा देखकर सब बच्चे हंसने लगे। टीचर ने हंसने का कारण पूछा तो सभी ने रिवकू की पेंट की तरफ इशारा किया। क्लास टीचर ने उसकी पेंट पर छपे शब्दों को पढ़ा तो बड़ी हैरान हुई। पूछा कि ये किसकी शरारत है, तो सभी चुप थे। रिवकू बेचारा यह लिखा देखकर शर्मिंदगी महसूस कर रहा था। क्लास टीचर का ध्यान जब चीनू और पोपू की तरफ गया तो वे दोनों नीचे निगाहें किए हुए थे। क्लास टीचर समझ गई थी कि यह इन्हीं दोनों की शरारत होगी। बाद में उन दोनों ने मान लिया कि यह उन्हीं की शरारत है। क्लास टीचर ने उन्हें वार्निंग (चेतावनी) देकर छोड़ दिया था। कुछ दिन बाद चीनू और पोपू को फिर शरारत सूझी। रिवकू का दोस्त मीकू रोजाना अच्छी-अच्छी स्वादिष्ट चीजें घर से अपने टिफिन में लेकर आता था। मीकू रिवकू के साथ ही अपना खाना शेयर करता था और चीनू-पोपू को दिखा-दिखाकर खाना खाता था। पोपू ने चीनू से कहा कि अबकी बार मीकू को मजा चखाया जाए और यह मजा मैं चखाऊंगा। ये बड़ा हमें अपना खाना दिखा-दिखा कर खाता है और चिढ़ाता है। दोनों ने योजना बनाई कि इसके टिफिन में कुछ ऐसा रखा जाए कि इसे नानी याद आ जाए। दोनों आपस में विचार कर ही रहे थे कि क्या रखा जाए कि तभी पोपू के दिमाग में एक आइडिया आ गया।



इस सेंक्चुरी में संरक्षित रखे जाते हैं गधे

तुमने बाघ, शेर, चिड़ियों और गैंडों को बचाने के लिए, उन्हें सुरक्षित रखने के लिए सेंक्चुरी बनाने का बात तो सुनी होगी! पर क्या तुम्हें पता है कि भारत में एक ऐसी सेंक्चुरी है, जो जंगली गधों के लिए संरक्षित है? यह सेंक्चुरी बनाई गई है गुजरात के कच्छ में। यह इंडियन वाइल्ड लाइफ सेंक्चुरी करीब पांच हजार वर्ग किलोमीटर क्षेत्र में फैली हुई है और इसीलिए यह भारत की सबसे बड़ी वाइल्ड लाइफ सेंक्चुरी है। गुजरात में इन जंगली गधों को घुड़खर कहा जाता है। ये कद में आम गधों से ऊंचे होते हैं। ये कच्छ में मिलने वाले घास और पेड़ों के पत्ते आदि खाकर अपना गुजारा करते हैं। यह जानकर तुम्हें हैरानी होगी कि ये जंगली गधे 70 से 80 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से दौड़ सकते हैं। पहली बार 1940 में जब इन गधों की गिनती कराई गई, तब ये देश भर में साढ़े तीन हजार से ज्यादा की संख्या में थे। परंतु 20 साल के अंदर ही उनकी संख्या घटकर केवल साढ़े तीन सौ रह गई। इसके बाद इन्हें बचाने के लिए सेंक्चुरी बनाने का फैसला किया गया। फिर 1972 में यह बनकर तैयार हुई। आज इन घुड़खर की संख्या अच्छी-खासी है।

पाजामा पहनते हैं यहां के गधे

फ्रांस के सेंट मार्टिन हार्बर पर गधों को पाजामा पहनाने का अनोखा प्रचलन है। यहां हर साल बहुत से देशी-विदेशी सैलानी आते हैं। सबके आकर्षण का केंद्र होते हैं गधे, जो रंग-बिरंगे सूती कपड़े के पाजामे पहने होते हैं। बच्चे इन गधों पर टीक वैसे ही सवारी करते हैं, जैसे घोड़ों पर की जाती है। दरअसल इन गधों को पाजामा पहनाने की प्रथा इसलिए शुरू की गई, क्योंकि यहां की नमकीन दलदली जमीन पर मक्खी और मच्छर ज्यादा है। गधों को उनके काटने से बचाने के लिए उन्हें पाजामा पहनाया जाता है।



उसने चीनू से कहा कि कल स्पोर्ट्स पीरियड में मीकू के टिफिन को खाली करके उसमें हरी-हरी घास भरनी है। दूसरे दिन अपनी योजना के अनुसार पोपू कुछ घास और दो-चार हरी मिर्च ले आया। इंटरवल से पहले स्पोर्ट्स पीरियड था तो सभी बच्चे प्लेग्राउंड में जाने लगे। मीकू भी रिवकू के साथ चला गया। तभी पोपू और चीनू दोनों ने मिलकर उसका टिफिन खाली करके उसमें हरी मिर्च और घास भर दी और उसके टिफिन में जो भी चीजें थीं, सब जल्दी से खा-पीकर बराबर कर दी। इसके बाद वे दोनों प्लेग्राउंड में चले गये। जब इंटरवल समाप्त हुआ तो सभी बच्चे क्लास में आकर अपने-अपने टिफिन खोलकर लंच करने लगे। चीनू और पोपू भी अपना लंच कर रहे थे। मीकू ने अपना टिफिन खोला तो उसे देखकर भौचक्का रह गया। सभी बच्चे उसके टिफिन में घास देखकर हंसने लगे और कमेंट करने लगे कि आज तो जानवरों का खाना लेकर आए हो। इधर चीनू और पोपू बड़े मजे से कुछ इस तरह से लंच कर रहे थे, जैसे वे मीनू और रिवकू को चिढ़ा रहे हों। उन्होंने कुछ सहानुभूति दिखाते हुए और आश्चर्य करके मीकू से कहा कि यह जरूर किसी की शरारत है। आओ आज हमारे साथ लंच कर लो। मीकू मन ही मन सोच रहा था कि यह किसकी शरारत हो सकती है, तभी रिवकू ने इशारा किया कि यह इन दोनों का ही काम हो सकता है, क्योंकि इन्होंने मेरे साथ भी शरारत की थी। जब क्लास टीचर क्लास में आई तो बच्चों ने उन्हें मीकू के टिफिन में घास वाली बात बताई। टीचर पहले तो थोड़ा मुस्कराई, फिर गुर्रसे में बोली- ‘ये किसका काम है?’ चीनू और पोपू क्लास टीचर के सामने तो बहुत सीधे बन जाते थे, लेकिन टीचर के जाते ही शरारतें शुरू कर देते थे। अभी दोनों एकदम शांत थे। टीचर की निगाह जब इन दोनों पर गई तो पहले तो उन्होंने कहा कि हमने यह काम नहीं किया, लेकिन जब टीचर ने सही बात बताने पर दबाव डाला तो उन्होंने अपनी गलती मान ली। टीचर चीनू और पोपू को अपने कमरे में ले गई और उनसे प्यार से पूछा कि वे ऐसी शरारतें क्यों करते हैं तो उन्होंने बताया- ‘जो हमें किसी बात पर चिढ़ाता है तो बहुत बुरा लगता है। हम उससे बदला ले लेते हैं। मीकू जब रिवकू के साथ लंच करता था तो अपना खाना शेयर कराने की बजाए हमें दिखा-दिखाकर खाता था और चिढ़ाता था। और रिवकू जब भी कोई नई शर्ट या पेंट पहनता तो हमें चिढ़ाता और अपने को ऐसा शो करता जैसे कि वो क्लास का हीरो हो। हमें ये अच्छा नहीं लगा, इसीलिए हमने ऐसा किया।’ क्लास टीचर ने उन्हें बड़े प्यार से समझाया कि अब वे आगे से ऐसी कोई हरकत नहीं करें, जिससे किसी बच्चे को कोई परेशानी हो और क्लास में भी सब बच्चों को समझाया कि सभी बच्चे आपस में मिल-जुल्कर रहें। कोई किसी को किसी बात पर न चिढ़ाए। अगले दिन मीकू और रिवकू इंटरवल में लंच करने लगे तो उन्होंने चीनू और पोपू को भी लंच शेयर करने के लिए बुला लिया। अब चारों साथ-साथ ही लंच करते थे और बड़े अच्छे दोस्त बन गये थे। चीनू और पोपू की शरारतें भी अब कुछ कम होने लगी थीं।

पीएम मोदी सहित कई नेताओं ने किया भगत सिंह को नमन

नई दिल्ली। देश के महान क्रांतिकारी और अमर बलिदानी शहीद-ए-आजम भगत सिंह की जयंती पर आज पूरे देश ने उन्हें भावभीनी श्रद्धांजलि दी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, लोकसभा स्पीकर ओम बिरला समेत केंद्र सरकार के कई मंत्रियों और भाजपा के वरिष्ठ नेताओं ने उनके अदम्य साहस और सर्वोच्च बलिदान को याद किया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर पोस्ट करते हुए लिखा, शहीद भगत सिंह को उनकी जयंती पर कोटि-कोटि नमन। अपने अदम्य साहस और शौर्य से उन्होंने आजादी के आंदोलन को नई धार दी। राष्ट्र के सम्मान के लिए सर्वस्व न्योछावर करने का उनका जज्बा भारत के नौजवानों की हिम्मत और हौसले का प्रतीक है। पीएम मोदी ने एक वीडियो संदेश भी जारी किया। उन्होंने कहा, अमर शहीद भगत सिंह हर भारतवासी विप्लवकर युवाओं के लिए एक प्रेरणापुंज हैं। निर्भीकता उनके स्वभाव में कूट-कूटकर भरी थी। देश के लिए फांसी के फंदे पर झूलने से पहले भगत सिंह ने अंग्रेजों को पत्र भी लिखा।

ममता और ऋतब्रत के गुटों को चार हफ्ते की मोहलत

नई दिल्ली। तृणमूल कांग्रेस के नाम और चुनाव चिह्न जोड़ा घास फूल चुनाव चिह्न को लेकर पार्टी के दो प्रतिद्वंद्वी गुटों के बीच चल रहे विवाद पर सुप्रीम कोर्ट ने सोमवार को चुनाव आयोग को फैसला करने के लिए समय सीमा तय कर दी। शीर्ष अदालत ने दोनों गुटों को चुनाव आयोग के समक्ष अपनी दलीलें और दस्तावेज चार सप्ताह के भीतर पूरा करने का निर्देश दिया है। मुख्य न्यायाधीश सूर्यकांत, न्यायमूर्ति जॉयमाल्या बागची और न्यायमूर्ति वी. मोहना की पीठ ने कहा कि दोनों पक्षों को दलीलें पूरी होने के बाद चुनाव आयोग तीन महीने के भीतर विवाद पर फैसला करे। सुप्रीम कोर्ट ने यह आदेश पश्चिम बंगाल की पूर्व मुख्यमंत्री ममता बनर्जी की उस याचिका पर सुनवाई के दौरान दिया, जिसमें उन्होंने चुनाव आयोग के उस फैसले को चुनौती दी है, जिसके तहत तृणमूल कांग्रेस के मूल नाम और उसके आरक्षित चुनाव चिह्न को फिलहाल इस्तेमाल करने पर रोक लगाई गई है।

भाजपा सरकार ने मदरसों के साथ भेदभाव किया: अखिलेश

लखनऊ। अखिलेश यादव ने सोमवार को लखनऊ में प्रेसवार्ता की। उन्होंने कहा कि इस सरकार को कोई और दूसरा काम नहीं करना है। इनको सिर्फ लोगों को बांटना है। मदरसों के साथ इन्होंने भेदभाव किया है। भाजपा को सिर्फ तोड़ना आता है। आधी-अधूरी नौकरी और आधी-अधूरी शिक्षा देने का काम भाजपा ने किया था। हमारी सरकार आने पर सारी व्यवस्था ठीक कर देंगे। आने वाले समय हम शिक्षा मित्रों को और बेहतर बनाने का काम करेंगे। उनको एक शिक्षक के रूप में सम्मानित करेंगे। सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव ने कहा कि 2022 के विधानसभा चुनाव में चुनाव आयोग की गड़बड़ी के कारण सपा की सरकार यूपी में नहीं बन सकी। उन्होंने कहा कि चुनाव के बाद हमने कहा था कि सपा समर्थकों के वोट काटे गए। 2017 में हम समझ नहीं सके। हम मानते थे कि चुनाव आयोग ईमानदारी से और निष्पक्ष होकर काम कर रहा होगा पर ऐसा नहीं था।

उत्तरप्रदेश में 150 सीटों पर अड़ी कांग्रेस

नईदिल्ली। 2027 के विधानसभा चुनावों से पहले, कांग्रेस ने उत्तर प्रदेश में सीट-शेयरिंग को लेकर अपनी उम्मीदें साफ कर दी हैं। राज्य के प्रभारी राजेंद्र पाल गौतम ने कहा है कि पार्टी गठबंधन के तहत 150 से कम सीटों पर चुनाव नहीं लड़ेगी। गौतम ने बताया कि कांग्रेस और उसके सहयोगी दलों के बीच सीट-शेयरिंग का समझौता अक्टूबर में फाइनल होने की उम्मीद है। उनके इस बयान से 403 सदस्यों वाली उत्तर प्रदेश विधानसभा में कांग्रेस की संभावित हिस्सेदारी की एक निश्चित संख्या सामने आई है, जिससे संकेत मिलता है कि पार्टी समाजवादी पार्टी के साथ चुनावी गठबंधन में अहम भूमिका निभाना चाहती है। उत्तर प्रदेश में कांग्रेस और सपा, इंडिया गठबंधन के मुख्य सहयोगी दल हैं। इन दोनों पार्टियों ने राज्य में 2024 के लोकसभा चुनावों के लिए साथ मिलकर काम किया था और अब वे 2027 में होने वाले बड़े चुनावी मुकाबले की तैयारी कर रही हैं। गौतम ने कहा कि कांग्रेस पिछले दो महीनों से सीट-शेयरिंग की प्रक्रिया की तैयारी कर रही है।

चुनाव आयोग का एसआईआर फैसला सामूहिक था: सीएम पेमा

ईटानगर। अरुणाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री पेमा खांडू ने सोमवार को कहा कि निर्वाचन आयोग के अपने रिकॉर्ड से स्पष्ट है कि मतदाता सूचियों का विशेष गहन पुनरीक्षण (एसआईआर) किसी एक व्यक्ति का नहीं बल्कि आयोग का सामूहिक फैसला था। कांग्रेस नेता राहुल गांधी की ओर से कई बार यह सवाल उठाए जाने पर कि क्या एसआईआर का फैसला एकतरफा था, खांडू ने कहा कि भारत निर्वाचन आयोग ने स्पष्ट किया है कि इस कवायद से संबंधित 24 जून 2025 का आदेश ‘‘आयोग की सर्वसम्मत् मंजूरी’’ से जारी किया गया था। खांडू ने ‘एक्स’ पर एक पोस्ट में कहा, ‘‘राहुल गांधी ने कई बार सवाल उठाया है कि क्या एसआईआर एकतरफा फैसला था। निर्वाचन आयोग का स्वयं का रिकॉर्ड अब इसका स्पष्ट संस्थागत जवाब देता है।’’ उन्होंने कहा, ‘‘आधिकारिक रिकॉर्ड स्पष्ट है। एसआईआर आयोग का फैसला था, किसी एक व्यक्ति का नहीं।’’ खांडू ने यह भी कहा कि एसआईआर से संबंधित बाद के कार्यक्रमों को भी आयोग की सर्वसम्मत् मंजूरी मिली थी, और आधिकारिक रिकॉर्ड से स्थिति पूरी तरह स्पष्ट है।

विपक्ष के आरोपों पर केंद्रीय मंत्री जेपी नड्डा का पलटवार

‘झूठ सौ बार बोलने से सच नहीं बनता’ देश का माहौल खराब करने की कोशिश

नई दिल्ली। केंद्रीय मंत्री जेपी नड्डा ने सोमवार को चुनाव आयोग पर विपक्ष के आरोपों की कड़ी आलोचना की। उन्होंने कहा कि चुनाव आयोग ने विपक्ष के सभी झूठों का पर्दाफाश कर दिया है। विपक्षी नेताओं पर जनता को गुमराह करने और देश में भ्रम पैदा करने की कोशिश करने का आरोप लगाया।

पत्रकारों से बात करते हुए नड्डा ने कहा कि तथ्यों की कसौटी पर परखने पर विपक्ष के आरोप बार-बार खारिज किए गए हैं। उन्होंने दावा किया कि उनके आरोपों की सच्चाई चुनाव आयोग और देश की सर्वोच्च अदालतों के सामने भी आ चुकी है। नड्डा ने कहा, अब चुनाव आयोग ने सारे झूठ बेनकाब कर दिए हैं। उन्होंने विपक्ष पर आरोप लगाया कि चुनाव आयोग के सभी सदस्यों के जवाब देने के बावजूद वे आरोप लगाते रहते हैं।

उन्होंने लोकसभा में विपक्ष के नेता राहुल गांधी और आम आदमी पार्टी के राष्ट्रीय संयोजक अरविंद केजरीवाल पर भी निशाना साधा। उन्होंने कहा, राहुल गांधी और अरविंद केजरीवाल आरोप लगाते हैं और चले जाते हैं। उन्हें जनहित से कोई लेना-देना नहीं है।

केंद्रीय मंत्री ने कहा कि जब विपक्ष के पास इरादा और विजन की कमी होती है, तो वे देश में भ्रम पैदा करने और माहौल खराब करने की कोशिश करते हैं। नड्डा ने कहा, हमने कुछ दिन पहले देखा कि कैसे एक मगनद्वंद्व खबर के आधार पर देश भर में माहौल खराब करने की कोशिश की गई थी। अब, चुनाव आयोग के सभी सदस्यों द्वारा उनके आरोपों का जवाब दिए जाने के बाद भी, वे एक बार फिर देश का माहौल खराब करने की कोशिशों में लगे हुए हैं।

राहुल गांधी पर सीधा निशाना साधते हुए नड्डा ने कहा, राहुल गांधी, ध्यान से सुनिए किसी झूठ को सौ बार दोहराने से वह सच नहीं बन जाता, और सच को कभी हराया नहीं जा सकता। नड्डा ने आगे आरोप लगाया कि राहुल गांधी, अरविंद केजरीवाल, अखिलेश यादव और ममता बनर्जी समेत विपक्ष के नेताओं की राजनीति संवैधानिक और स्वायत्त संस्थाओं पर सवाल उठाने तक ही सिमटती

जा रही है। उन्होंने कहा, आरोप लगाना, भ्रम फैलाना, देश का माहौल खराब करना और फिर भाग जाना यही उनके काम करने का तरीका बन गया है। नड्डा ने सत्ता के प्रति और विपक्ष के नजरिए में भी अंतर बताया और कहा कि पार्टी सत्ता को जनता की सेवा का जरिया मानती है।

नड्डा ने कहा, भाजपा के लिए सत्ता 140 करोड़ लोगों के हितों की सेवा करने का माध्यम है। उन्होंने कहा कि भाजपा का मकसद देश के नागरिकों की सेवा करना और अंत्योदय के प्रति अपनी प्रतिबद्धता को पूरा करना है, जबकि विपक्ष पर वंशवादी राजनीति और अपने निजी हितों के लिए सत्ता हासिल करने की कोशिश करने का आरोप लगाया।

केंद्रीय मंत्री ने कहा कि जनता विपक्ष के दोहरे मापदंडों और नकारात्मक राजनीति को समझ चुकी है। इसके साथ ही जोर देकर कहा कि अस्थिरता पैदा करने की किसी भी कोशिश का जवाब जनता लोकतांत्रिक तरीके से देगी। नड्डा का यह बयान कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खरगे के उस आरोप के बाद आया है जिसमें उन्होंने कहा था कि सीईसी, भाजपा की विचारधारा को बढ़ावा दे रहे हैं।

कांग्रेस का केंद्र सरकार पर हमला

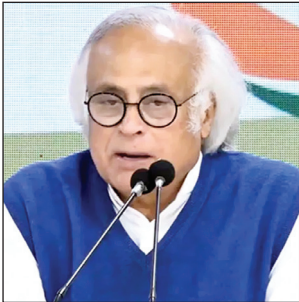
‘मन की बात में महंगाई पर कब होगी चर्चा? मोदी से पूछे सवाल

नई दिल्ली। कांग्रेस ने सोमवार को इलेक्ट्रॉनिक सामानों की बढ़ती कीमतों को लेकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर निशाना साधा। पार्टी ने कहा कि वे अपने मन की बात कार्यक्रम में कई मुद्दों पर उपदेश देते रहते हैं, लेकिन देश की सबसे बड़ी चिंता महंगाई पर कब बात करेंगे?

कांग्रेस के संचार विभाग के प्रभारी महासचिव जयराम रमेश ने एक मीडिया रिपोर्ट का स्क्रीनशॉट शेयर किया। इस रिपोर्ट में दावा किया गया है कि त्योहारों के मौसम से पहले एलईडी टीवी और वॉशिंग मशीन जैसे कई इलेक्ट्रॉनिक सामान महंगे होने वाले हैं। कंपनियां तांबा और एल्युमीनियम जैसे कच्चे माल की बढ़ती लागत के कारण 1 अक्टूबर से कीमतें 5% से 10% तक बढ़ाने की तैयारी कर रही हैं।

रमेश ने एक्स (पहले ट्विटर) पर पोस्ट किया, त्योहारों के मौसम में जनता को लूटने का सिलसिला बेरोकटोक जारी है। महंगाई की मार अब सिर्फ रसोई तक सीमित नहीं रही है, फिर भी प्रधानमंत्री बेफिक्र होकर अपनी ही तापीयों के पुल बांध रहे हैं। सन्नियां दिन-ब-दिन महंगी होती जा रही हैं। अगस्त में प्याज की कीमतें 48.27% तक बढ़ गईं। वहीं, एयर कंडीशनर, टीवी व रेफ्रिजरेटर जैसी चीजों की कीमतें भी बढ़ने वाली हैं।

रमेश ने दावा किया कि परिवारों की बचत लगातार घट रही है, जबकि उन पर कर्ज का बोझ



बढ़ रहा है। उन्होंने सवाल किया कि ऐसे हालात में एक आम परिवार अपनी जरूरतें कैसे पूरी करेगा? उन्होंने कहा, प्रधानमंत्री अपनी मन की बात रडियो सीरीज में कई मुद्दों पर उपदेश देते रहते हैं, लेकिन देश की सबसे बड़ी चिंता महंगाई पर कब बात करेंगे? वे जनता की चिंताओं की परवाह कब करेंगे?

उन्होंने कहा कि जनता पहले से ही बढ़ती कीमतों से परेशान है। सरकार की ओर से कोई राहत नहीं मिल रही है। रमेश ने कहा, मध्यम वर्ग और गरीबों को कमर ऐसे बोझ से कब तक टूटती रहेगी? बता दें कि कांग्रेस जरूरी चीजों और घरेलू सामानों की बढ़ती कीमतों को लेकर सरकार पर लगातार हमला कर रही है। इसके साथ ही सरकार से आम आदमी पर बोझ कम करने की मांग कर रही है। हालांकि, सरकार ने जीडीपी के आंकड़ों का हवाला देते हुए कांग्रेस के दावों को खारिज कर दिया है और कहा है कि अर्थव्यवस्था तेजी से बढ़ रही है।

अरविंद केजरीवाल पर बरसे दिल्ली के मंत्री, कहा-

गुंडागर्दी से नहीं जीता जाता जनता का दिल : प्रवेश वर्मा

नईदिल्ली। दिल्ली के पीडब्ल्यूडी मंत्री प्रवेश वर्मा ने तिलक नगर में सड़क के निरीक्षण के दौरान हुई एक हालिया घटना को लेकर आम आदमी पार्टी के राष्ट्रीय संयोजक अरविंद केजरीवाल की कड़ी आलोचना की। उन्होंने आरोप लगाया कि जिस व्यक्ति ने उनसे बहस की, वह जेनरेशन जेड का सदस्य नहीं, बल्कि आप से जुड़ा एक गुंडा था। एक्स पर एक वीडियो पोस्ट करते हुए वर्मा ने कहा कि वह आप विधायक जरनैल सिंह की शिकायतों के बाद उस जगह पर गए थे और दिल्ली सरकार द्वारा किए जा रहे कामों के बारे में जानकारी देना चाहते थे। उन्होंने कहा कि केजरीवाल जी, मैं आपको सिखा सकता हूँ कि जनता का दिल कैसे जीता जाता है। लेकिन यह तभी हो सकता है जब आपके पास अपने ड्रामे से फुर्सत हो। पहले यह वीडियो देखिए!

वर्मा ने केजरीवाल के पुराने बर्ताव की आलोचना करते हुए कहा कि बच्चों की झूठी कसम खाना, वोटिंग के दिन इमोशनल कार्ड खेलने के लिए बुजुर्ग माता-पिता को व्हीलचेयर पर बिठाना, शीश महल में महिला सांसद के साथ मारपीट करना और दिल्ली के मुख्य सचिव की पिटाई करना—ये सब उनकी आदत बन गई थी। और अब, वे जेन-जी का बहाना बना रहे हैं। उन्होंने आगे कहा कि केजरीवाल जी, कल मेरे इलाके में जो व्यक्ति आया था, वह जेन-जी नहीं था; वह आपका गुंडा था। आपका विधायक कई गुंडों के साथ वहां पहुंचा था। मैं उसे प्यार से समझाना चाहता था कि हम किस तरह का काम कर रहे हैं। आपके कोर्टों की शिकायत थी, तो मैं उन शिकायतों को सुनने और उनका समाधान करने के लिए वहां गया था।

वर्मा ने कहा कि शायद यह पहला मौका है जब किसी विपक्षी विधायक की शिकायत के बाद कोई मंत्री खुद मौके पर जाकर समाधान करने की कोशिश कर रहा है। उन्होंने आगे कहा कि अगर



आप इन बातों को नहीं समझ पा रहे हैं, तो इसकी वजह यह है कि 15 सालों तक आपने न तो दिल्ली में सड़कें बनाई और न ही कोई विकास का काम किया। केजरीवाल जी, मैं आपको बताना चाहता हूँ कि आपका यह जेन जी वाला ड्रामा काम नहीं आएगा।

उन्से सवाल-जवाब करने वाले व्यक्ति का चित्र करते हुए वर्मा ने दावा किया कि तीन महीने पहले उस व्यक्ति के ख़िलाफ़ मुनिसिपल कॉर्पोरेशन ऑफ़ दिल्ली (एमसीडी) के एक कॉन्स्ट्रक्ट कर्मचारी के साथ मारपीट करने के आरोप में एफआईआर दर्ज की गई थी। उन्होंने आरोप लगाया कि उसने एमसीडी के एक कॉन्स्ट्रक्ट कर्मचारी की गर्दन तोड़ दी थी। उस एफआईआर में जरनैल सिंह के भतीजे का नाम भी शामिल है। हमारी दिल्ली पुलिस ने उन दोनों को गिरफ्तार किया था। और बाद में, आपने उस बेचारे कॉन्स्ट्रक्ट कर्मचारी का घर और दुकान तक तुड़वाने की कोशिश की। वर्मा ने चेतावनी दी कि वह दिल्ली सरकार के काम में रुकावट या अधिकारियों और कॉन्स्ट्रक्टर्स को परेशान करने की हरकत बर्दाश्त नहीं करेंगे। उन्होंने कहा कि अगर आप आज वहाँ जा रहे हैं, तो जरूर जाएँ। अपने साथ अपने सभी गुंडों को भी ले जाएँ। जितना चाहें उतना ड्रामा करें, लेकिन मेरे सामने आपकी गुंडागर्दी बिल्कुल नहीं चलेगी।

स्टेल प्रमुख समाचार

शूटर ईशा सिंह ने पिस्टल फाइनल में सिल्वर मेडल जीता

नागोया। शूटर ईशा सिंह ने रोमांचक 25 मीटर पिस्टल फाइनल में सिल्वर मेडल जीत लिया है। भारतीय कुराश खिलाड़ी पिंकी बलहारा को एशियाई खेलों में महिलाओं के 78 किलो सेमीफाइनल में कांस्य जीत लिया है। ईशा सिंह का क्या शानदार प्रदर्शन रहा! नाथ कोरिया की किम ह्योन सुक के खिलाफ लगातार तीन शूट-ऑफ से गुज़रकर फाइनल मुकाबले तक पहुँचने के बाद ईशा ने महिलाओं की 25 मीटर पिस्टल फाइनल में शानदार सिल्वर मेडल जीता। गोल्ड मेडल के लिए भी चीन की शियाओ जियारइक्सुआन के साथ दो शूट-ऑफ में मुकाबला करना पड़ा। सिंगरस पिस्टल इवेंट में भारत का यह पहला मेडल है!

भारत की पिंकी बलहारा ने सोमवार को यहां महिला 78 किग्रा से कम भार वर्ग की कुराश स्पर्धा के सेमीफाइनल में दक्षिण कोरिया की सुमिन मो से 0-5 से हारकर कांस्य पदक अपने नाम किया। मुकाबले के दौरान पिंकी को डब्की (पेनल्टी) मिली, जबकि मो ने योनबोश किए हासिल किया। यह एशियाई खेलों में पिंकी का दूसरा पदक है। उन्होंने 2018 के जकार्ता एशियाई खेलों में महिलाओं के 52 किग्रा से कम भार वर्ग में रजत पदक जीता था। उस खेल में कुराश को पहली बार एशियाई खेलों में शामिल किया गया था। इससे पहले पिंकी ने दक्षिण कोरिया की लिय गारा को 3-0 से हराकर सेमीफाइनल में जगह पक्की की थी। इस 27 वर्षीय भारतीय खिलाड़ी ने निर्णायक अंक चाला के एरिए हासिल किया, जबकि लिय पूरे मुकाबले में जकि भी अंक नहीं जुटा सकी। चाला तब दिया जाता है, जब खिलाड़ी प्रतिद्वंद्वी को जमीन पर गिराता है, लेकिन इस दांव में पूरा नियंत्रण नहीं होता। भारतीय पुरुष स्कॉश टीम ने सोमवार को एशियाई खेलों के अपने अभियान की शानदार शुरुआत करते हुए पूल ए में चीन को 3-0 से हराया।

आर्थिक/वाणिज्य/विज्ञान/

प्रमुख समाचार

सैंसेक्स 1,124 अंक और निफ्टी 360 अंक टूटकर बंद हुए

मुंबई। भारतीय शेयर बाजार के लिए आज का दिन बेहद निराशाजनक रहा। वैश्विक स्तर पर बढ़ते भू-राजनीतिक तनाव और कच्चे तेल की आसमान छूती कीमतों के कारण घरेलू शेयर बाजार में हाहाकार मच गया। चौतरफा बिकवाली के दबाव में आकर बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज का मुख्य सूचकांक सेंसेक्स 1,124.02 अंक (1.52%) टूटकर 72,771.72 के स्तर पर बंद हुआ। वहीं, नेशनल स्टॉक एक्सचेंज का निफ्टी भी 360.25 अंक (1.56%) की बड़ी गिरावट के साथ 22,780.25 पर सिमट गया। आज की इस गिरावट से निवेशकों के लाखों करोड़ रुपये स्वाहा हो गए। डॉलर की मजबूती और महंगे कच्चे तेल के दबाव में भारतीय रुपया भी आज 0.19% कमजोर होकर प्रति डॉलर 96.00 के स्तर पर बंद हुआ। बाजार में गिरावट इतनी व्यापक थी कि बड़े शेयरों के साथ-साथ छोटे और मझोले शेयरों में भी भारी बिकवाली हुई।

सात शहरों में जुलाई-सितंबर में मकानों की बिक्री 3% बढ़ी

नई दिल्ली। देश के सात प्रमुख शहरों में जुलाई-सितंबर के दौरान मकानों की बिक्री सालाना आधार पर 3 प्रतिशत बढ़कर एक लाख इकाई से अधिक हो गई। मुंबई महानगर क्षेत्र, बेंगलुरु और हैदराबाद में मजबूत मांग इसकी मुख्य वजह रही। रियल एस्टेट सलाहकार कंपनी अनारॉक ने यह जानकारी दी। अनारॉक के अनुसार, मूल्य के लिहाज से जुलाई-सितंबर के दौरान कुल बिक्री 2% बढ़कर 1.55 लाख करोड़ रुपए हो गई, जो पिछले साल की समान अवधि में 1.52 लाख करोड़ रुपए थी। गौरतलब है कि रियल एस्टेट डेटा एनालिटिक्स कंपनी प्रॉपर्टिक्रिटी ने पिछले सप्ताह कहा था कि जुलाई-सितंबर तिमाही में कुल बिक्री छह प्रतिशत घटकर 1.03 लाख इकाई रह गई। रियल एस्टेट सलाहकार अनारॉक ने सोमवार को जुलाई-सितंबर तिमाही के प्राथमिक आवासीय बाजार के आंकड़े जारी किए।

तेल की धार पर दुनियाँ की अर्थव्यवस्था के लिए अगले 7 दिन निर्णायक!

किशन सनमुखदास भावनानी वैश्विक अर्थव्यवस्था सितंबर 2026 के अंतिम सप्ताह में ऐसे मोड़ पर खड़ी दिखाई दे रही है,जहां युद्ध, कूटनीति, ऊर्जा सुरक्षा, व्यापार शुल्क, महत्वपूर्ण खनिज, समुद्री मार्ग और शेयर बाजार एक-दूसरे से गहराई से जुड़ गए हैं। एक ओर ईरान ने अमेरिका के सामने होर्मुज़ जलडमरूमध्य में सामान्य समुद्री आवागमन बहाल करने के लिए सात-दिवसीय प्रस्ताव रखा है, तो दूसरी ओर अमेरिकी राष्ट्रपति और चीनी राष्ट्रपति की वाशिंगटन वार्ता ने दुनियाँ की दो सबसे बड़ी अर्थव्यवस्थाओं के व्यापारिक रिश्तों में नए समीकरण खड़े किए हैं।इसी बीच कच्चे तेल की ऊंची कीमतों ने भारत जैसे बड़े तेल आयातक देशों की चिंता बढ़ा दी है और 24 सितंबर को भारतीय शेयर बाजार में भारी बिकवाली देखने को मिली। इसलिए आने वाले कुछ दिन केवल पश्चिम एशिया की

राजनीति के लिए नहीं,बल्कि तेल की कीमत, समुद्री व्यापार, महंगाई, मुद्रा बाजार और वैश्विक निवेश धारणा के लिए भी अत्यंत महत्वपूर्ण हो सकते हैं। मैं यह मानता हूँ कि विश्व अर्थव्यवस्था की थड़कने इस समय फास की खाड़ी के उस संकरे समुद्री द्वार पर टिकी है, जिसे होर्मुज़ जलडमरूमध्य कहा जाता है। अमेरिका- ईरान टकराव के बीच तेहरान ने ऐसा सात-दिवसीय प्रस्ताव सामने रखा है,जिसके अंतर्गत अमेरिकी सैन्य एवं आर्थिक दबाव में राहत सहित निर्धारित शर्तें पूरी होने पर होर्मुज़ में सामान्य समुद्री आवागमन बहाल किया जा सकता है। अमेरिकी और ईरान के प्रतिनिधियों के बीच चरणबद्ध समाधान पर बातचीत की खबरें भी सामने आई हैं, लेकिन अंतिम समझौता अभी अनिश्चित है। यही अनिश्चितता वैश्विक ऊर्जा बाजार के लिए सबसे बड़ा जोखिम बन गई है। होर्मुज़ का संकेत केवल तेल उत्पादक



देशों की समस्या नहीं है। यहां व्यवधान का अर्थ है,ऊर्जा आपूर्ति पर दबाव, जहाजरानी और बीमा लागत में वृद्धि, महंगा कच्चा तेल और अंततः दुनिया भर में महंगाई का खतरा। 26 सितंबर को कूटनीतिक समाधान की उम्मीदों से ब्रेट कच्चा तेल करीब दो प्रतिशत फिसलकर लगभग 104.30 डॉलर प्रति बैरल तक आया,लेकिन कीमत अभी भी ऊंचे स्तर पर है।खाड़ी-ए-ओमान में जहाज से जहाज तेल हस्तांतरण क्षमता भी अपनी सीमा तक पहुंचने की खबर है,जो आपूर्ति व्यवस्था पर दबाव की गंभीरता दर्शाती है।भारत के लिए यह संकेत विशेष महत्व रखता है। महंगा तेल आयात बिल बढ़ा सकता है, रुपये पर दबाव

डाल सकता है तथा परिवहन और उत्पादन लागत के रास्ते महंगाई को प्रभावित कर सकता है।तेल कीमतों की अस्थिरता के बीच रुपया 22 सितंबर को 95.59 प्रति डॉलर पर बंद हुआ था; वहीं भारतीय शेयर बाजार लगातार सातवें सप्ताह नुकसान में है। साथियों, सबसे पहले होर्मुज़ जलडमरूमध्य की बात करें तो 25 सितंबर को संयुक्त राष्ट्र में ईरान के विदेश मंत्री ने कहा कि तेहरान ने अमेरिका को इस रणनीतिक समुद्री मार्ग को खोलने के लिए एक ठोस सात-दिवसीय परिजना दी है। उनके अनुसार आवश्यक परिस्थितियां पूरी होने पर सात दिनों के भीतर सामान्य समुद्री आवागमन बहाल किया जा सकता है और अब निर्णय अमेरिका के हाथ में है। उन्होंने यह भी कहा कि अमेरिकी पक्ष से अपेक्षित कदम नए नहीं हैं,बल्कि जून में अमेरिका और ईरान के बीच हुए समझौता जापान से जुड़े हैं।हालांकि 26

सितंबर तक स्थिति अनिश्चित बनी हुई है।अमेरिकी राष्ट्रपति द्वारा प्रस्ताव को अस्वीकार किए जाने की मीडिया रिपोर्ट सामने आई है,लेकिन ईरान आधिकारिक अमेरिकी प्रतिक्रिया की प्रतीक्षा कर रहा है।इसलिए इस समय यह कहना जल्दबाजी होगी कि सात दिनों के भीतर संकेत समाप्त हो जाएगा;इतना जरूर है कि प्रस्ताव ने कूटनीतिक समाधान की एक नई खिड़की खोली है।होर्मुज़ का सवाल इतना महत्वपूर्ण इसलिए है क्योंकि यह केवल ईरान और अमेरिका के बीच शक्ति-संघर्ष का विषय नहीं, बल्कि वैश्विक ऊर्जा अर्थव्यवस्था की संवेदनीयता नस है।तनाव बढ़ने पर जहाजरानी,बीमा ऊर्जा आपूर्ति और परिवहन लागत प्रभावित होने का जोखिम बढ़ता है, जबकि तनाव घटने और सामान्य आवागमन बहाल होने की संभावना तेल बाजार को राहत दे सकती है।

बस्तर के बाढ़ प्रभावित क्षेत्रों में पहुंचे मुख्यमंत्री साय, प्रभावित परिवारों से मिलकर जाना हाल

संकट की इस घड़ी में हर प्रभावित परिवार के साथ मजबूती से खड़ी है सरकार : साय

बाढ़ के बाद शुद्ध पेयजल, स्वास्थ्य सुविधाओं और जलजनित बीमारियों की रोकथाम पर विशेष ध्यान देने को कहा

रायपुर। मुख्यमंत्री वणु देव साय ने आज बस्तर जिले के बाढ़ प्रभावित क्षेत्रों का दौरा कर जमीनी स्थिति का जायजा लिया। मुख्यमंत्री श्री साय जगदलपुर नगर निगम क्षेत्र के डोंगाघाट पहुंचे और बाढ़ से प्रभावित परिवारों से आत्मीयतापूर्वक मुलाकात कर उनकी समस्याएं सुनीं। उन्होंने प्रभावित लोगों को आश्वासन दिया कि संकट की इस घड़ी में राज्य सरकार उनके साथ पूरी संवेदनशीलता और तत्परता से खड़ी है तथा प्रत्येक प्रभावित परिवार को हरसंभव सहायता उपलब्ध कराई जाएगी।

मुख्यमंत्री श्री साय ने बाढ़ प्रभावित परिवारों को बड़ी राहत देते हुए शासन के प्रावधानों के तहत मिलने वाली सहायता के अतिरिक्त प्रत्येक प्रभावित परिवार को मुख्यमंत्री राहत कोष से 210-10 हजार की सहायता राशि प्रदान करने की घोषणा की।



उन्होंने अधिकारियों को निर्देश दिए कि बाढ़ से हुई क्षति का सर्वे और आकलन तेजी से पूरा कर पात्र परिवारों तक शासन की सहायता शीघ्र पहुंचाई जाए। मुख्यमंत्री श्री साय ने डोंगाघाट में बाढ़ प्रभावित परिवारों से मुलाकात की। उन्होंने प्रभावितों से बाढ़ के दौरान उत्पन्न परिस्थितियों, मकानों एवं घरेलू सामान को हुए नुकसान तथा वर्तमान में उपलब्ध कराई जा रही राहत के संबंध में जानकारी ली। मुख्यमंत्री ने कहा कि प्रभावित परिवारों की आवश्यकताओं को ध्यान में रखते हुए हर जरूरी सहायता उपलब्ध कराएगी। मुख्यमंत्री ने अधिकारियों को स्पष्ट

निर्देश दिए कि राहत कार्यों में किसी प्रकार की शिथिलता न हो। भोजन, स्वच्छ पेयजल, दवाइयां और अन्य आवश्यक सामग्री प्रभावित लोगों तक समय पर पहुंचाई जाए। विशेष रूप से बच्चों, बुजुर्गों, महिलाओं तथा जरूरतमंद लोगों की आवश्यकताओं का ध्यान रखते हुए राहत व्यवस्था सुनिश्चित की जाए। मुख्यमंत्री श्री साय ने अधिकारियों से कहा कि बाढ़ का पानी कम होने के बाद प्रभावित क्षेत्रों में स्वास्थ्य एवं स्वच्छता से जुड़ी चुनौतियों पर विशेष ध्यान दिया जाए। लोगों को शुद्ध पेयजल उपलब्ध कराना सुनिश्चित किया जाए।

इंद्रावती के जलस्तर और प्रभावित इलाकों का किया अवलोकन मुख्यमंत्री श्री साय ने इंद्रावती पुल पहुंचकर नदी के जलस्तर तथा आसपास के बाढ़ प्रभावित क्षेत्रों का अवलोकन किया। उन्होंने विभागीय अधिकारियों से जिले में बारिश एवं बाढ़ की स्थिति, प्रभावित गांवों और शहरी क्षेत्रों, राहत एवं बचाव कार्यों तथा प्रभावित परिवारों के लिए की गई व्यवस्थाओं की जानकारी ली। मुख्यमंत्री ने कहा कि जलस्तर में बदलाव और मौसम की स्थिति पर लगातार निगरानी रखी जाए। निचले एवं संवेदनशील क्षेत्रों में विशेष सतर्कता बरती जाए तथा आवश्यकता पड़ने पर राहत एवं बचाव दलों को तत्काल सक्रिय किया जाए। उन्होंने कहा कि लोगों की सुरक्षा सर्वोपरि है और किसी भी आपात स्थिति में सहायता पहुंचाने की व्यवस्था पूरी तरह तैयार रहनी चाहिए।

विश्व पर्यटन दिवस पर जिले को मिला

‘सर्वश्रेष्ठ जिला प्रमोशन अवॉर्ड’



पुरासांस्कृतिक धरोहर ‘धनपुर’ पर आधारित कॉफी टेबल बुक का हुआ विमोचन

गौरेला-पेंड्रा-मरवाही। जिले ने पर्यटन के क्षेत्र में एक महत्वपूर्ण उपलब्धि हासिल की है। जिले में पर्यटन को बढ़ावा देने तथा यहां की समृद्ध प्राकृतिक, ऐतिहासिक, पुरातात्विक एवं सांस्कृतिक विरासत को प्रभावी ढंग से देश-दुनिया के सामने प्रस्तुत करने के उद्देश्यनय प्रयासों के लिए छत्तीसगढ़ टूरिज्म बोर्ड द्वारा जीपीएम जिले को ‘सर्वश्रेष्ठ जिला प्रमोशन अवॉर्ड’ से सम्मानित किया गया।

राजधानी रायपुर में 27 सितंबर को विश्व पर्यटन दिवस के अवसर पर छत्तीसगढ़ टूरिज्म बोर्ड एवं ‘छत्तीसगढ़ ट्रेवल ट्रेड एसोसिएशन’ (सीजीटीटीए) के संयुक्त तत्वावधान में आयोजित ‘सैंट्रल इंडिया कनेक्ट मार्केटप्लेस’ के दौरान जिले को यह प्रतिष्ठित सम्मान प्रदान किया गया। इस अवसर पर जिले की महत्वपूर्ण पुरातात्विक एवं सांस्कृतिक धरोहर ‘धनपुर’ पर आधारित आकर्षक कॉफी टेबल बुक का भी विमोचन किया गया।

भारतीदासन, छत्तीसगढ़ टूरिज्म बोर्ड के प्रबंध संचालक श्री सोमिल रंजन चौबे, कलेक्टर जीपीएम श्री विजय दयाराम के. तथा जिला पंचायत के मुख्य कार्यपालन अधिकारी श्री सुकेश रावटे द्वारा किया गया। धनपुर की पुरातात्विक एवं सांस्कृतिक विशेषताओं को समर्पित इस कॉफी टेबल बुक में क्षेत्र के ऐतिहासिक महत्व, पुरातात्विक धरोहर और पर्यटन संभावनाओं को आकर्षक एवं प्रभावी ढंग से प्रस्तुत किया गया है। यह पहल धनपुर को प्रदेश और देश के पर्यटन मानचित्र पर नई पहचान दिलाने के साथ ही जीपीएम जिले की अन्य पर्यटन एवं सांस्कृतिक धरोहरों के प्रति पर्यटकों की रुचि बढ़ाने में भी सहायक होगी।

शतरंज की बिसात पर भारत का डबल धमाका

ओपन में रजत व महिला वर्ग में कांस्य पदक

रायपुर। वित्त मंत्री ओपी चौधरी ने उज्बेकिस्तान के समरकंद में आयोजित 46वें खट्टुश्व चैस ओलंपियाड 2026 में भारतीय खिलाड़ियों के शानदार प्रदर्शन पर पूरी टीम को हार्दिक बधाई एवं शुभकामनाएं दी हैं। भारत ने ओपन वर्ग में रजत पदक और महिला वर्ग में कांस्य पदक हासिल कर विश्व शतरंज के मंच पर देश का गौरव बढ़ाया है।



है। ओपन वर्ग में रजत और महिला वर्ग में कांस्य पदक देश की शतरंज प्रतिभाओं की उत्कृष्टता को दर्शाता है। भारत ने ओपन और महिला वर्ग के संयुक्त प्रदर्शन के आधार पर प्रतिष्ठित नोना ग्रेण्डमास्टर ट्रॉफी भी अपने नाम की। यह लगातार तीसरा चैस ओलंपियाड

खिलाड़ियों की ये उपलब्धियां देश की नई पीढ़ी को शतरंज से जुड़ने और विश्व स्तर पर उत्कृष्ट प्रदर्शन करने के लिए प्रेरित करेंगी। उन्होंने भारतीय दल के सभी खिलाड़ियों, प्रशिक्षकों और सहयोगी सदस्यों को बधाई देते हुए उनके उज्ज्वल भविष्य की कामना की।

सेवा संकल्प अभियान में गांव-गांव स्वच्छता की मुहिम रायपुर। सेवा संकल्प अभियान एवं स्वच्छता ही सेवा-2026 के अंतर्गत जांगीर-चांपा जिले के गांवों में जनभागीदारी के साथ स्वच्छता की मुहिम चलाई जा रही है। ‘स्वच्छता में सहभागी, स्वच्छ भारत विकसित भारत’ की थीम पर ग्रामीण क्षेत्रों में श्रमदान, सार्वजनिक स्थलों एवं तालाबों की सफाई, पौधरोपण और हाथ धुलाई जैसी गतिविधियों के माध्यम से स्वच्छता, स्वास्थ्य और पर्यावरण संरक्षण का संदेश जन-जन तक पहुंचाया गया।

छत्तीसगढ़ हॉकी लीग : चयन ट्रायल के

पहले दिन 223 खिलाड़ी उतरे मैदान पर

उप मुख्यमंत्री अरुण साव ने खिलाड़ियों से की मुलाकात

रायपुर। छत्तीसगढ़ हॉकी लीग (सीएचएल) के पहले सीजन के लिए खिलाड़ियों का चयन ट्रायल आज रायपुर के सरदार वल्लभ भाई पटेल अंतरराष्ट्रीय हॉकी स्टेडियम के पिच-1 पर शुरू हुआ। ट्रायल के लिए पंजीकृत 373 खिलाड़ियों में से 223 खिलाड़ियों ने पहले दिन उपस्थित होकर ट्रायल में भाग लिया।



युवा कल्याण मंत्री अरुण साव ने ट्रायल स्थल पहुंचकर खिलाड़ियों की हौसला अफजाई की। उन्होंने

मैदान पर खिलाड़ियों से मुलाकात की और उनसे बातचीत की। उन्होंने कहा कि छत्तीसगढ़ में हॉकी को

जड़ें बहुत गहरी हैं। इस ट्रायल में खिलाड़ियों का उत्साह इसका प्रमाण है। आज मैंने मैदान पर स्वयं उनके जुनून को देखा। छत्तीसगढ़ हॉकी लीग का उद्देश्य ऐसे ही युवा खिलाड़ियों को एक बड़ा मंच देना है, जहाँ वे राष्ट्रीय और अंतरराष्ट्रीय स्तर के खिलाड़ियों के साथ मैदान साझा करेंगे। हमारा लक्ष्य है कि छत्तीसगढ़ की हर खेल प्रतिभा को राज्य, राष्ट्रीय और अंतरराष्ट्रीय स्तर तक आगे बढ़ने का अवसर मिले। उन्होंने ट्रायल में भाग ले रहे खिलाड़ियों शुभकामनाएं दीं।

चित्रकला प्रतियोगिता के लिए 15 विद्यार्थी चयनित बिलासपुर। सेवा से संकल्प अभियान’ के अंतर्गत विकासखंड स्तरीय भाषण प्रतियोगिता का आयोजन पीएम श्री सेजेस गर्ल्स स्कूल, सरकंडा में किया गया। प्रतियोगिता में विकासखंड के ग्रामीण एवं शहरी क्षेत्रों के 60 संकुलों से प्रथम स्थान प्राप्त करने वाले छात्र-छात्राओं ने उत्साहपूर्वक भाग लिया। प्रतियोगिता में उत्कृष्ट प्रदर्शन करने वाले ‘5 विद्यार्थियों का भाषण तथा 10 विद्यार्थियों का चित्रकला प्रतियोगिता के लिए जिला स्तरीय प्रतियोगिता हेतु चयन किया गया। विद्यार्थियों ने स्वच्छ भारत, नया कश्मीर, महिला सशक्तिकरण, सेना का शौर्य और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस जैसे विषयों पर अपने विचार प्रभावशाली ढंग से प्रस्तुत किए। प्रतियोगिता में ‘अमितेश तिवारी (डीएवी स्कूल, बसंत बिहार), रिमझिम ठाकुर (एनएफबी स्पर्श विद्यालय, तिफरा), रूपाली श्रीवास (एमएस देवरीखुर्द), रागिनी मित्रा (एमएस रहंगी) और अनुराधा सूर्यवंशी (एमएस मोहता) ’ का जिला स्तरीय प्रतियोगिता के लिए चयन हुआ। अमितेश तिवारी ने ‘स्वच्छ भारत, सपनों का भारत’ विषय पर औद्योगिकीकरण एवं नगरीकरण को स्वच्छता के समक्ष चुनौती बताते हुए स्वच्छ भारत के निर्माण में प्रत्येक व्यक्ति की सहभागिता को आवश्यक बताया।

पीएम आवास योजना ग्रामीण में 74 हजार से अधिक हितग्राही पात्र

रायपुर। प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण अंतर्गत आवास प्लस 2.0 (2024) सर्वे के आधार पर सिस्टम जनरेट प्राथमिकता सूची का ग्रामसभा में अनुमोदन किया गया है। अनुमोदित सूची के अनुसार रायपुर जिले के चार जनपदों में कुल 75 हजार 461 हितग्राहियों में से 74 हजार 68 हितग्राही पात्र तथा 1 हजार 393 हितग्राही अपात्र पाए गए हैं। जिला पंचायत रायपुर से जारी प्रस्तुत कर सकते हैं। दावा-आपत्ति ग्रामसभा में आमंत्रित की गई है। निर्धारित समयावधि में प्राप्त लिखित आवेदनों पर जिला स्तरीय समिति द्वारा नियमानुसार विचार किया जाएगा। जिला पंचायत ने स्पष्ट किया है कि समय-सीमा के बाद प्राप्त, त्रुटिपूर्ण अथवा असम्पन्न आवेदनों पर विचार नहीं किया जाएगा। पात्र एवं अपात्र हितग्राहियों की सूची संबंधित जिला कार्यालय, विकासखंड कार्यालय एवं ग्राम पंचायत भवन के सूचना पटल पर अवलोकन के लिए चस्पा की गई है।

बेलटुकरी में आंगन मिलन उत्सव का आयोजन

बिलासपुर। सेवा संकल्प अभियान के तहत आज परियोजना कार्यालय मस्तूरी के आंगनबाड़ी केंद्र बेलटुकरी क्रमांक-2 में ‘आंगन मिलन उत्सव’ का आयोजन किया गया। कार्यक्रम में पूर्व कैबिनेट मंत्री एवं पूर्व विधायक डॉ. कृष्णमूर्ति बांधी विशेष रूप से मौजूद थे। इसके अलावा श्री चंद्रप्रकाश सूर्या सहित स्थानीय जनप्रतिनिधि एवं गणमान्य नागरिक उपस्थित रहे। आंगनबाड़ी केंद्र में ‘न्योता भोज’ का आयोजन किया गया, जिसमें अतिथियों द्वारा बच्चों को भोजन कराया गया। इस अवसर पर ‘हर घर मुनगा-घर-घर मुनगा’ का संदेश देते हुए डॉ. बांधी ने ‘आंगनबाड़ी-एक मुनगा पेड़’ थीम के तहत आंगनबाड़ी केंद्र परिसर में मुनगा पौधे का रोपण किया। महिला एवं बाल विकास विभाग द्वारा स्थानीय व्यंजनों एवं विभिन्न भाजियों की प्रदर्शनी भी लगाई गई। मुख्य अतिथि ने प्रदर्शनी का उद्घाटन एवं अवलोकन किया तथा स्थानीय पोषण आधारित खाद्य पदार्थों को दैनिक आहार में शामिल करने के महत्व पर जानकारी ली। कार्यक्रम की शुरुआत माता सरस्वती की पूजा-अर्चना एवं दीप प्रज्वलन से हुई। अतिथियों का पुष्पगुच्छ के साथ स्वागत किया गया।

राज्य स्तरीय रोजगार मेला 7 एवं 8 अक्टूबर को रायपुर में

रायपुर। मुख्यमंत्री विष्णु देव साय के नेतृत्व में प्रदेश के युवाओं को उनकी योग्यता और कौशल के अनुरूप रोजगार से जोड़ने की दिशा में राज्य सरकार द्वारा लगातार प्रयास किए जा रहे हैं। इसी कड़ी में कौशल विकास, तकनीकी शिक्षा एवं रोजगार विभाग द्वारा 07 एवं 08 अक्टूबर 2026 को सरदार बलबीर सिंह जुनेजा इंडोर स्टेडियम, बूढ़ापारा, रायपुर में दो दिवसीय वृहद राज्यस्तरीय रोजगार मेले का आयोजन किया जा रहा है। रोजगार मेले के दूसरे दिन 08 अक्टूबर को मुख्यमंत्री श्री विष्णु देव साय के मुख्य आतिथ्य में चयनित युवाओं को ऑफर लेटर वितरित किए जाने प्रस्तावित हैं। रोजगार मेले के माध्यम से प्रदेश के शिक्षित एवं प्रशिक्षित युवाओं को स्थानीय उद्योगों के साथ राष्ट्रीय स्तर की कंपनियों में रोजगार के अवसर उपलब्ध कराने का प्रयास किया जा रहा है। राज्यस्तरीय रोजगार मेले के लिए विभिन्न औद्योगिक प्रतिष्ठानों, कंपनियों एवं प्लेसमेंट संस्थाओं से रिक्तियों का संकलन लगातार किया जा रहा है। अब तक 36 नियोजकों एवं प्लेसमेंट संस्थाओं से कुल 8,720 रिक्त पदों की जानकारी प्राप्त हो चुकी है। उपलब्ध रिक्तियों को ई-रोजगार पोर्टल पर प्रदर्शित किया जा रहा है, ताकि अभ्यर्थी अपनी योग्यता एवं रुचि के अनुसार पदों का चयन कर ऑनलाइन आवेदन कर सकें। अन्य प्रमुख औद्योगिक एवं व्यावसायिक प्रतिष्ठानों से भी संपर्क किया जा रहा है।

पचपेड़ी महाविद्यालय में स्वेच्छिक रक्तदान शिविर

बिलासपुर। संत गुरु घासीदास कला, विज्ञान एवं शिक्षा महाविद्यालय पचपेड़ी एवं राष्ट्रीय सेवा योजना इकाई द्वारा ‘सेवा संकल्प अभियान’ के तहत आज महाविद्यालय परिसर में स्वेच्छिक रक्तदान शिविर का आयोजन किया गया। हंसवाहिनी सेवा समिति के छायाचित्र पर माल्यापण एवं दीप प्रज्वलन कर किया। महाविद्यालय के प्राचार्य डॉ. आर.के. जायसी ने अतिथियों का सादर एवं श्रीफल से सम्मान किया। उन्होंने स्वयं रक्तदान कर विद्यार्थियों एवं उपस्थित लोगों को स्वेच्छिक रक्तदान के लिए प्रेरित किया।

तीन दिवसीय यूथ इनोवेशन एवं एंटरप्रेन्योरशिप कॉन्क्लेव का शुभारंभ

विचारों को उद्यम में बदलने युवा : रमोन डेका

रायपुर। राज्यपाल श्री रमोन डेका ने कहा कि युवाओं को सिर्फ नौकरी पाने के बारे में नहीं सोचना चाहिए, बल्कि अपने विचारों को उद्यम में बदलने का साहस भी रखना चाहिए। एक अच्छा विचार, सही मार्गदर्शन और उद्युक्त तकनीक के साथ आगे बढ़े तो वही नवाचार सफल स्टार्टअप का रूप ले सकता है और आगे चलकर अनेक लोगों के लिए रोजगार का माध्यम बन सकता है।



व्यवसायीकरण को बढ़ावा देने के उद्देश्य से आयोजित तीन दिवसीय ‘यूथ इनोवेशन एवं एंटरप्रेन्योरशिप कॉन्क्लेव-2026’ के शुभारंभ समारोह को संबोधित

कर रहे थे। इस अवसर उन्होंने विश्वविद्यालय में स्थापित सुभाष चंद्र बोस बायोटेक्नोलॉजी इन्व्यूबेशन सेंटर का लोकार्पण भी किया।

राज्यपाल ने कहा कि हर क्षेत्र में नवाचार की आवश्यकता है। छत्तीसगढ़ में कृषि के क्षेत्र में नवाचार की व्यापक संभावनाएं हैं। देश की बढ़ती आबादी की खाद्यान्न आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए उत्पादन बढ़ाने के साथ नई तकनीकों और नए प्रयोगों को अपनाना जरूरी है। उन्होंने कहा कि प्रत्येक राज्य के लिए आवश्यक मूलभूत खाद्य पदार्थों के उत्पादन में आत्मनिर्भरता महत्वपूर्ण है। जब हमारी खाद्य आवश्यकताएं सुरक्षित होंगी, तभी हम विकास के अन्य क्षेत्रों पर अधिक प्रभावी ढंग से ध्यान केंद्रित कर सकेंगे। उन्होंने कहा कि छत्तीसगढ़ में

नवाचार की सबसे बड़ी संभावनाएं हमारे अपने संसाधनों में हैं। कृषि, वनोपज, खाद्य प्रसंस्करण, मिलेट, जैविक खेती, पशुपालन और जनजातीय उत्पादों जैसे क्षेत्रों में युवाओं के लिए अपार अवसर हैं। कृषि और जैव-प्रौद्योगिकी राज्य के विकास में महत्वपूर्ण भूमिका निभा सकते हैं। राज्यपाल ने कहा कि आज ऐसे नवाचारों की आवश्यकता है, जो किसानों की लागत कम करें, उत्पादन और गुणवत्ता बढ़ाएं, फसल के नुकसान को कम करें तथा किसानों को उनकी उपज का बेहतर मूल्य और बाजार उपलब्ध कराने में मदद करें।

मंत्री लक्ष्मी राजवाड़े ने भारत गौरव टूरिस्ट ट्रेन को दिखाई हरी झंडी

रायपुर। मुख्यमंत्री तीर्थ दर्शन योजना के अंतर्गत आज रायपुर रेलवे स्टेशन से भारत गौरव टूरिस्ट ट्रेन तीर्थयात्रियों को लेकर रवाना हुई। महिला एवं बाल विकास तथा समाज कल्याण मंत्री श्रीमती लक्ष्मी राजवाड़े ने ट्रेन को हरी झंडी दिखाई। उन्होंने यात्रियों से आत्मीय संवाद किया और उन्हें सुखद, सुरक्षित एवं मंगलमय यात्रा की शुभकामनाएं दीं। यह यात्रा 28 सितंबर से 1 अक्टूबर 2026 तक आयोजित है। इस दौरान श्रद्धालु महाराष्ट्र के शिर्डी में साई बाबा, शनि शिंगणापुर में शनिदेव तथा ल्यंबकेश्वर ज्योतिर्लिंग के दर्शन करेंगे। प्रस्थान से पहले रायपुर



रेलवे स्टेशन पर तीर्थयात्रियों में उत्साह दिखाई दिया। मंत्री श्रीमती राजवाड़े ने कहा कि मुख्यमंत्री तीर्थ दर्शन योजना उन वरिष्ठ नागरिकों के लिए विशेष अवसर है, जो वर्षों से तीर्थयात्रा की इच्छा रखते हैं, लेकिन विभिन्न परिस्थितियों के

कारण यात्रा नहीं कर पाते। उन्होंने कहा कि तीर्थ दर्शन आस्था और सांस्कृतिक जुड़ाव का अनुभव है। राज्य सरकार का प्रयास है कि पात्र हितग्राही आवश्यक सुविधाओं के साथ सहज और सुरक्षित वातावरण में तीर्थस्थलों के दर्शन कर सकें।